is the meaning of it and whether the Government abides by that Resolution or is under an obligation to implement it. You should tell us. Otherwise it is impossible to get on. What is the use of passing a Resolution when the Government ignores it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You can refer to all these points when you speak on the President's address.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : You should give your opinion.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Let us proceed with the next business.

SHRI BHUPESH GUPTA : You may not give your opinion just now but I want to place this before you. Here is a Resolution passed by this House. Now this Resolution is the property of the House. The Protection of this Resolution and respect for it is a task that goes to you, Sir. Now I should like to know from the Chair what view the Chair takes of this Resolution. I should like to know from the Chair whether it is valid or invalid and how the Chair views the reactions or behaviour of the Government in relation to this Resolution. Today it is Tuesday. The Budget will be presented on Saturday at 5 O'Clock. The Resolution says that legislative and other steps should be completed before the presentation of the Budget. I should like to know from the Chair in what manner this Resolution is going to be given effect to and how we should called upon to pass the necessary legislation as enjoined by the Resolution. These are my submissions.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is already five minutes past three and it will not be proper to go on any more with this when there is the Short Duration Discussion fixed for 3 P.M.

SHRIMATI YASHODA REDDY : The negotiations are not connected with the abolition of the privy purses ; they are to see how far the Princes are giong to support the Indira Gandhi Government. The negotiations are not about this Resolution.

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : This is a serious charge and therefore the matter has to be gone into by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now I pass on to the next business. Dr. Bhai Mahavir.

SHRI NIREN GHOSH : Unless the Chair is seized of the matter in the coming day or the day after, there is going to be trouble.

SHRI BHUPESH GUPTA : Why this kind of generous treatment to the former Princes who are up against this Government ? Because this Government has supporters in them in Rajasthan military has been called to attack the poor peasants in the Ganganagar area. Womenfolk have been malested. People have been shot. Houses have been raided. Government act in that vindictive manner and with such expedition against the poor peasants there. And when it comes to the Princes, they negotiate transitional arrangements for them. We are not going to put up with this insult. We want the Bill based on this Resolution to be brought here tomorrow.

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu) : On a point of order, Sir. Mr. Bhupesh Gupta and other people are unnecessarily wasting the time to the House now discussing the abolition of the privy purses. They should discuss it with the Minister and not take the time of the House like this.

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Order please. There is no question of any point of order. The Chair had allowed Mr. Das to refer to the question, and he has done it. Now we must proceed with the next business. Dr. Bhai Mahavir.

SHORT DURATION DISCUSSION UNDER RULE 176 *RE* ROLE OF GOVERNORS IN RELATION TO FORMATION OF MINISTRIES IN THE CONTEXT OF RECENT HAPPENINGS IN UTTAR PRADESH AND BIHAR AND THE CONSTITUTIONAL IMPLICATIONS THEREOF

डा० भाई महावीर (दिल्ली) : उपसभापति महोदय, मैं आज सदन में एक ऐसे महत्व के विषय पर चर्चा प्रारंभ करने लगा हूं, जो आज

[डा० भाई महावीर]

की सरकार को थोड़े समय के लिये अपनी मर्जी के अनुसार तय हो गया दिखाई देता होगा। लेकिन उसमें अपने देश के भविष्य के लिये जिस तरह के अनिश्चिता के, जिस तरह के संदेह के और जिस तरह के गड़बड़ी के बीज विद्यमान हैं, उनकी ओर अगर कोई ध्यान देगा उसे तो अपने देश में लोकतंत्र के भविष्य के बारे में चिन्ता होने लगेगी ।

जब मैं संविधान को देखता हूं, तो मुझे एक बात उसमें ऐसी विशेष मालूम होती है कि जिसका जिक्र कर के मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगा । हमारे संविधान में देश के हर पद के लिये कोई न कोई स्थान ऐसा है, जहां पर कि वह जिम्मेदार ठहराया जायगा, जहां पर कि उसे अपने कृत्यों, अपने कार्यों के लिये जवाब देह होना पड़ेगा । राष्ट्रपति, अपने देश के सबसे ऊंचे आसन पर जो विराजमान हों उनको भी संविधान के अनुसार चलना पड़ता है और यदि किसी समय संविधान के विरुद्ध वह जायं, तो उनको इम्पीचमेंट का डर रहता है और यह सदन उनको भी इम्पीच कर सकता है । उसकी पद्धति संविधान के अन्दर है और इसलिये राष्ट्रपति के सामने भी यह सवाल होता है कि उनके लिये संविधान की रक्षा करते हुए उनके ऐसा न करने पर क्या परिस्थिति पैदा हो सकती है, यह वह भूल नहीं सकते । लेकिन हमारे देश के अन्दर राज्यपाल एक ऐसा पद है गवर्नर का एक ऐसा स्थान है जो कि कहीं भी जवाब देह मालूम नहीं होता। वह एक राज्य का भाग है, हैड आफ स्टेट है, लेकिन उस राज्य में उसको जवाब देह होने को जरूरत नहीं, वहां पर वह इम्यून है असेम्बली के सामने अपने किसी काम के बारे में, अपने किसी फैसले के बारे में कुछ पूछा जा सके और वह बताये ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती और केन्द्र में हम पूछ सकें गवर्नर के लिये हमें यह भी अधिकार नहीं है । जब कभी गवर्नर कुछ कहते हैं, तब हमें जवाब दिया जाता है, उन्होने अपने डिसक्रिशन का इस्तेमाल किया और संविधान उनको वह डिसक्रिशन इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। जिस समय संविधान बना होगा, उस समय यह सोचा गया होगा कि अगर गवर्नर कुछ करेंगे तो उनके किसी भी कार्य को, उनके किसी भी फैसले को केन्द्रीय सरकार अपना फैसला बता कर, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी और जो कुछ भी पूछना होगा, उसका जवाब केन्द्रीय सरकार, केन्द्र के गृह मंत्री देंगे, लेकिन ऐसा होने के बजाय केन्द्रीय सरकार ऐसे मौके पर यह कह कर के छूट जाती है कि जो कुछ गवर्नर ने किया संविधान में मिले हुए अपने विवेक डिसक्रशिन का इस्तेमाल कर के किया है, केन्द्र उसके लिये जवाब देह नहीं। इस परिस्थिति का परिणाम क्या हुआ है, यह यदि हम देखें तो पिछले आम चुनावों के बाद से हमारे देश के अन्दर तरह-तरह की परिस्थितियों के दृश्य सामने आये ऐसे दृश्य आये जहां पर, जैसे एक जगह राजस्थान में बहुमत सुखाडिया जी को नहीं मिला, लेकिन जब विरोधी दलों ने मिल कर यह कहा कि असेम्बली का, विधान सभा का, अधिवेशन बुलाया जाये और उसमें देखा जाये कि जो दल संविद बना था, वह एक बहुमत लेकर आ सकता है या नही, वहां पर राज्यपाल ने संविद के कहने के बाद भी और उसका स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी, वहां पर विधान सभा का अधिवेशन बुलाने की बजाय उसको स्थगित किया और सुखाडिया जी को एक मौका दिया कि वह जिसको बहुमत प्राप्त है, उसको स्पष्ट कर दे, स्पष्ट शब्दों में, "हार्स ट्रेडिंग" जिसको कहा जाता है वैसा करके, लोगों को खरीद कर, कुछ लोगों को घसीट कर अपनी ओर ले जाये जहां पर राजस्थान में यह उदाहरण है कि विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया, वहां पर, दूसरा हमारे पास बंगाल का उदाहरण है, जहां पर विधान सभा का अधिवेशन न बुलाने के कारण वहां की सरकार को भंग किया। किस लिए भंग किया ? 20 दिन वह सरकार अपना अधिवेशन जल्दी बुलाने के लिये तैयार नहीं हुई, इस लिये उसको भंग कर दिया गया। मुझे यहां पर कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वहां पर संविद की जो

सरकार थी या जो आज है, उसकी किसी बात में मैं सहमत नहीं हूं । लेकिन एक बात से मैं अपने को सहमत पाता हूं कि जिस बात के लिये वह दोशी है, वह यह कि उनका अपराध था कि उन्होंने नक्सलबाड़ी का वहां आंदोलन खड़ा किया, वहां पर ला एन्ड आर्डर की सिचुएशन खराब की, वहां पर उन्होंने चीन के साथ तालमेल रखने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया, वहां पर अन्याय और पुलिस की व्यवस्था को डिमोरेलाइज करके रखा, लेकिन हमारी केन्द्र की सरकार हाथों पर मैहदी लगाए बैठी रही। लेकिन गवर्नर ने फैसला कब किया। 20 दिन पहले असेम्बली का अधिवेशन नहीं होता, इस वास्ते उसको भंग कर दिया । मेरा निवेदन यह है कि हरियाणा की सरकार भंग की चव्हाण साहब ने यह कह कर कि वहां पर अस्थिरता है, आयाराम और गयाराम करते है, आयाराम की कीमत 10,000 है और गयाराम की कीमत 20,000 है । चव्हाण साहब ने यह काव्यपूर्ण नाम देकर सारे देश के साहित्य जगत में अपना नाम कमा लिया। मैं जानता हूं जहाँ कहीं आयाराम और गयाराम का जिक्र होता है, तो लोक चव्हाण साहब की साहित्यिक बुद्धि की तारीफ करते है । मुझे पूछना यह है कि हरियाणा में अगर इस तरह का आयाराम गयाराम होने के कारण वहां की सरकार को भंग किया गया, तो पंजाब में क्या किया गया ? पंजाब में जिस दिन, जिस क्षण चीफ मिनिस्टर सरदार गुरनाम सिह को यह लगा कि उनके दल को छोड़ कर गिल जा रहे हैं, वह बहुमत नहीं रखते, उन्होंने असेम्बली भंग करने की सिफारिश की और इस्तीफा दे दिया। लेकिन हमारी केन्द्र ने वहां पर गर्वनर के द्वारा असेम्बली को भंग करने की बजाय वहां पर एक माइनारिटी सरकार, एक कठपुतली सरकार पंजाब की छाती पर लाद कर रखी। वह सौदा मैं जानता हूं, कांग्रेस को महंगा पड़ा और अगर फिर से वैसी गल्तियां होंगी, तो मुझे विश्वास है कि जो एक बार गिरने से नहीं सीख सका, आज वह फिर से सीखने की उनको नौबत आयेगी । परन्तु मुझे इस समय उस पहलू में नहीं जाना । मुझे यह कहना है कि एक जगह पर अस्थिरता के कारण सरकार भंग की जाती है, दूसरी जगह अस्थिरता ला कर के एक माइनारिटी की सरकार बैठा कर रखी जाती है। एक जगह विधान सभा नहीं बुलाई जाती है, इसलिये विधान सभा भंग की गई, दूसरी जगह विधान सभा के बुलाने की मांग करने के बाद भी नहीं बुलाई गई । समय दिया गया ताकि अपनी मर्जी के मुख्य मंत्री को वहां लाया जा सके । इस तरह की बातें जो चलती रही हैं, इससे न केन्द्र की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, न इस देश के लोकतंत्र के भविष्य को उज्जवल किया है । लेकिन आज केन्द्र से जब हम यह पूछते हैं कि गवर्नरों को जो अधिकार दे रखे हैं, उसके अंतर्गत वे चाहे जो कर सकते हैं, क्या उनको पूछने वाला कोई नहीं है, तो हमें चव्हाण साहब ने जवाब दिया कि गवर्नर का यह काम है कि वह देखे कि बहुमत उस सरकार के पक्ष में होनी चाहिये, जो बनायी जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बहुमत जानने के लिये कोई गाइडिंग प्रिन्सिपल्स, गाइडिंग लाइन्स या गाइडिंग डायरेक्शन्स है गवर्नर के पास या नहीं हैं ? पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कुछ हुआ है, उसका अगर कोई अर्थ निकलता है, तो यह स्पष्ट है कि केन्द्र ने जान बूझ करके आज कोई स्पष्ट दिशाऐं नहीं दी है । ऐसा कोई स्पष्ट दिशा और निर्देश नहीं किया है। गवर्नरों को ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक हर परिस्थिति में लाभ उठाया जा सके । जो हुआ है यदि हम इसका विचार करें, तो हमारे सामने यह दिखायी देता है कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि 10 फरवरी को श्री चन्द्रभानु गुप्त ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने जो चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी के समर्थन में दूसरे और दल भी तीन चार थे, उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिह को बुलाया जाय; क्योंकि उन सारे दलों का समर्थन चरण सिह जी को होगा। लेकिन गवर्नर महोदय ने उस चिट्ठी के ऊपर कोई कार्यवाही करने की बजाय शांत बैठे रहे,

[डा भाई महावीर]

चुप रहे। कहा जाता है, मुझे यह कहीं से बताया गया कि चौधरी साहब ओथ लेने के लिये तैयार नहीं थे। मैंने वह अखबार देखा है, जिसमें गुप्त जी के इस्तीफे की खबर है, उसमें चौधरी चरण सिंह का ब्यान है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि : When summoned I will not flinch from the responsibility of the high office. लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। ही वाज नाट समन्ड। 10 तारीख के बाद 11 तारीख आई, उस दिन यह खबर निकली कि यू० पी० की मिनिस्ट्री के बारे में दो दिन के अंदर फैसला होगा। दो दिन की इंतजारी करनी पड़ी लोगों को। 12 तारीख को एक खबर निकली, जिसके बारे में बाद में कान्ट्रेडिक्शन जरूर आया है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, हमारे सरकार ने यहां जो लिखा है 'सत्यमेव जयते' क्या वह दिखावे के लिये है, क्या वह केवल ऊंचे स्थानों पर रखने के लिये है, क्या वह व्यवहार में लाने के लिये नहीं है। गवर्नर को जो बुलाया गया, इतनी बड़ी मोटी हैड-लाइन जिसकी है कि : डेल्ही समन्स यू० पी० गवर्नर, मैं समझता हूं स्टेटसमैन का 13 फरवरी का जो अखबार है इसमें, गवर्नर महोदय प्राइम मिनिस्टर महोदय के बुलाने पर दिल्ली आए हैं, यह स्पष्ट रूप से लिखा है। इतना ही नहीं, एक खबर है कि त्रिपाठी जी गवर्नर से वहां से चलने से पहले मिले हैं और त्रिपाठी जी ने कहा है कि मुझे गवर्नर ने बताया कि : He was still assessing the situation and had not yet come to any conclusion. अभी तक वह सारी स्थिति का विचार कर रहे हैं, किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। मुसीबत यही थी कि वह किसी फैसले पर उस वक्त तक नहीं पहुंचे थे। उनको फैसले पर पहुंचने के लिये दिल्ली बुलाया गया। वह दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद उन्होंने 15 तारीख को यह बयान दिया है कि वह दोनों पार्टियों के राइवल क्लेम्स का फैसला करेंगे, दोनों से राइवल क्लेम्स के बारे में तादाद मांगेंगे। मेरा निवेदन यह है 14 तारीख को दिल्ली में पहले उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि : No hustling: he will not allow himself to be hustled into any decision regarding Ministry-making. 16 तारीख को उन्होंने ब्रेक अप आफ दि पार्टीज मांगा, लेकिन 17 तारीख हुई साढ़े 9 बजे सुबह चौधरी चरण सिंह मिले गवर्नर को और उन्होंने अपनी लिस्ट दी। एक घण्टे बाद या डेढ़ घण्टे बाद गिरधारी लाल मिले, उन्होंने अपनी लिस्ट दी और सवा एक बजे गवर्नर ने यह फैसला कर लिया कि चौधरी चरण सिंह वजारत बनायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं : क्या गवर्नर के पास कोई ऐसा कम्प्यूटर रखा हुआ था कि जिसमें उत्तर प्रदेश विधान सभा के सारे मेम्बरों की आदतें उनका खानपान, उनके सोचने का तरीका, कहां सोते हैं, कहां जागते हैं, क्या सपना देखते हैं, किसको पसन्द करते हैं, किस रास्ते में जाना पसन्द करते हैं, कहां जाने में अपना फायदा महसूस करते हैं, क्या ये सारे कार्ड पन्च करके उनके कम्प्यूटर में लगा दिये थे कि जैसे लाइट आई कि उन्होंने बटन दबाया और जवाब मिल गया कि चौधरी चरण सिंह को पूरा बहुमत प्राप्त हो गया है और उनको वजारत बनाने का निमन्त्रण देना चाहिये। एक तरफ 11 बजे गिरधारी लाल गवर्नर को मिलने गये, जिस वक्त उनकी बातचीत हो रही थी, लखनऊ के लोग बताते हैं, ठीक उसी समय लखनऊ के अंदर जीपें घूम रही थीं और कहा जा रहा था कि 2 बज कर 40 मिनट पर चरण सिंह ओथ लेने वाले हैं। मुझे यह पूछने की इस वक्त जरूरत महसूस होती है कि इस 11 बजे और सवा एक बजे के बीच गवर्नर ने कैसे फैसला किया कि किसके साथ कितना बहुमत है और कितना नहीं है। सी० बी० गुप्त के इस्तीफे के बाद 4 दिन तक जब फैसला नहीं हो सका, तब एक घंटे के अंदर वह फैसला किसी जादू से कर लिया गया। वह जादू वहां पर श्री गोपाल रेड्डी के पास नहीं है, वह जादू यहां पर प्राइम मिनिस्टर के पास है। मुझे वहां से यह खबर मिली कि यहां प्राइम मिनिस्टर के पास

जब आए तो उसमें जो सरकारी कांग्रेस है, उसके नेता श्री बहुगुणा, श्री दीक्षित और गवर्नर प्रधान मंत्री के साथ एक कमरे में बंद डेढ़ घंटे तक वार्तालाप करते रहे। मैं समझता हूं उन्होंने कोई मौसम की चर्चा नहीं की होगी, उन्होंने यह नहीं कहा होगा कि दिल्ली के चिड़िया-घर में कितने-कितने शेर हैं, उन्होंने सफेद बच्चे कितने दिये हैं, काले बच्चे कितने दिये हैं। स्पष्ट है उन्होंने चर्चा यही की होगी कि उत्तर प्रदेश में अपनी गुट की सरकार बनाने के लिये क्या कोशिश की जा सकती है। गवर्नर को बुलाकर इस तरह से दबाव डालना यह केन्द्र सरकार को फायदे का सौदा नजर आता होगा, लेकिन यह हमेशा के लिये फायदे का सौदा नहीं है।

इसलिये केन्द्रीय सरकार को इस तरह की परम्पराएं और इस तरह के कन्वेंशन बनाने चाहियें, जो देश के लिये हितकर हों। आज केन्द्र में उनकी सरकार बैठी है, तो कल कोई दूसरी सरकार वहां पर बैठ सकती है। हमारा देश अमर रहने वाला है और कोई प्रधान मंत्री अमर रहने वाला नहीं है और कोई पार्टी अमर रहने वाली नही है। अगर कोई अमर रहने वाला है तो वह हमारा देश है, यहां की जनता है और हमारा राष्ट्र है। तो क्या हम अपने राष्ट्र के लिये कांटा बोना चाहते हैं; क्योंकि प्रधान मंत्री को ऐसा लगता है कि वे अपने ढींग हांकने के लिये सारे देश को बांट देना चाहती हैं। आज उन्होंने अपनी पार्टी के टुकड़े कर दिये हैं, यह उनके घर का मामला है और इसमें हमें कोई गिला नहीं है, लेकिन जिस वक्त इस तरह का फैसला करेंगी, इस तरह का काम करेंगी, जिससे देश के सामने गलत कन्वेंशन पैदा हो, गलत कन्वेंशन बने, तो यह स्वभाविक है कि देश हर लोकतंत्रीय व्यक्ति और दलों को इस बात की चिन्ता होगी कि इस लोकतंत्र में जो आने वाले दिन हैं, वह हम लोगों के वास्ते कठिनाई के दिन होंगे; क्योंकि हम सब लोगों को सोचना होगा कि प्रधान मंत्री क्यों ऐसा कर रही है, किन लोगों के भरोसे पर कर रही हैं और वे कौन सी-पार्टियां हैं जो इस तरह के काम करने में उन्हें हौसला दे रही हैं। आज हमें यह देखना है कि वे कौनसी पार्टियां हैं, जिनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और हमारे प्रधान मंत्री को भी सचमुच में इस बात को देखने की फुरसत नहीं है।

कल हमारे मित्र श्री मिश्रा जी ने बतलाया था कि किस तरह से इन्डोनेशिया के लोगों ने डा० सुकार्नो के ऊपर भरोसा करके देश को कहां से कहां पहुंचा दिया और किस गर्त में उन्होंने देश को डाल दिया। शायद हमारे प्रधान मंत्री को इस बात की चिन्ता नहीं है और न उनको इस बात की चिन्ता है कि जो सपोर्ट उन्हें मिल रही है, उसका क्या मतलब है। लेकिन ने कहा कि हम सपोर्ट ऐज दी "हैंगसमेन्स रोप" के रूप में करते हैं। इसी तरह का सपोर्ट आज प्रधान मंत्री को मिल रहा है और आज उन्हें इस सपोर्ट के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। आज इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि उनकी भलाई किसमें है। कौनसी चीज में किस तरह का सपोर्ट चाहिये, यह तो उनके विचार करने की बात है या फिर श्री चव्हाण के विचार करने की बात है। लेकिन जहां तक श्री चव्हाण साहब उनकी छत्र छाया में हैं वे शायद ही स्वतंत्र रूप से विचार करते होंगे। यह बात मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फैसला करना है। मेरा निवेदन यह है कि आज उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat) : The hangman is the right-hand man there.

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, बिहार में जो कुछ हुआ है, उसकी कहानी इस प्रकार है।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): After having taken the Maharaja of Gwalior, he is in top form now.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Do not interrupt him.

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, बिहार के गवर्नर की अपनी दूसरी कहानी है। बिहार गवर्नर के बारे में कहा जाता कि उन्होंने अपने

[डा० भाई महावीर]

डिसक्रिशन का इस्तेमाल किया है । गवर्नर जब अपने डिसक्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, तब जो दूसरे डिसक्रिशन होते हैं, वे सोये रहते हैं । जब हरिहर सिंह ने गवर्नर महोदय को अपनी पार्टी की ताकत की लिस्ट दी, तो वह गवर्नर महोदय की मेज पर अपने ऊपर धूल जमा करती रही और गवर्नर महोदय ने उसको देखने की भी जरूरत नहीं समझी । लेकिन जिस समय दरोगा राय लिस्ट लेकर आते हैं, तो उस समय गवर्नर महोदय के सामने डिसक्रिशन के इस्तेमाल करने का सवाल आ जाता है ताकि वे उस लिस्ट को देख कर अपने डिसक्रिशन का ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकें ।

उपसभापति महोदय, आपकी कृपा से हमें ये दो रिपोर्टें मिल गई हैं, जो गवर्नर ने प्रेसिडेंट साहब को भेजी है । पहली रिपोर्ट 10 फरवरी की है, जिसमें राष्ट्रपति को यह सिफारिश की गई है कि वे 6 महीने तक के लिये बिहार में राष्ट्रपति के शासन को जारी रखें, क्योंकि श्री दरोगा राय के पास कोई पक्की सबूत वजारत बनाने के लिए नहीं थी और उन्होंने कोई पक्का बहुमत प्राप्त नहीं किया था । लेकिन 14 फरवरी को सारी स्थिति बदल गई । जो दूसरी रिपोर्ट को पढ़ेगा, उसको मालूम हो जायेगा कि प्रधान मंत्री के साथी मंत्रीमंडल के जो सदस्य वहां पर उस समय विद्यमान थे, उन लोगों ने बाकी सब लोगों की वहां पर मदद की होगी । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस रिपोर्ट को भी ड्राफ्ट करने के लिये कोई आफिशियल वहां पर चला जाता, तो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट को ड्राफ्ट करके भेजता । इस रिपोर्ट में लिखा है कि श्री दरोगा प्रसाद राय हमारे पास आये और अपने साथ दो चिट्ठियां लाये । ये दो चिट्ठियां एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता की थी और एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता की थी ।

श्री अकबर अली खान (आंध्र प्रदेश) : क्या पहले चिट्ठियां नहीं थीं ।

डा० भाई महावीर : पहले चिट्ठी मौजूद नहीं थी लेकिन अब ये चिट्ठियां आई हैं, आप इस बारे में चिन्ता न कीजिए, मैं इन चिट्ठियों का जिक्र कर रहा हूं । इन दो चिट्ठियों में लिखा है : I have taken the following parties as dependable parties. Congress either (fraction), Samyukt Socialist Party, the Communist Party of India, Praja Socialist Party and the All India Jharkhand Party. मैं यह जानना चाहता हूं कि ये डिपेन्डेबिल पार्टियां कैसे हो गई और डिपेन्डेबिल की परिभाषा गवर्नर महोदय से पूछना चाहता हूं । मैं गवर्नर महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता नहीं है कि बिहार में भी जनसंघ कोई पार्टी है । जनसंघ जो वहां पर एक पार्टी के रूप में काम कर रही है उन्हें डिपेन्डेबिल पार्टी मालूम नहीं देती है । गवर्नर महोदय जिस तरह का दांवपेच वहां पर केन्द्र के इशारे पर करना चाहते थे, वह उन्होंने किया । गवर्नर महोदय ने यहां से मंत्रिमंडल के इशारे पर जो रोल अदा किया, उसमें वह कोई डिपेंडेबिल रोल अदा नहीं कर सके । यह बात भी ठीक है और हम इस चीज को मानने के लिये तैयार हैं । लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जनसंघ आपके हाथों का हथियार बनने के लिये तैयार नहीं है और आप अपने मतलब के मुताबिक उससे काम नहीं निकाल सकते हैं और न वह इसके लिये तैयार हैं ।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आगे इस चिट्ठी को देखा जाय जिसमें यह लिखा है :

The Jharkhand Party have supported the leadership of Shri Daroga Prasad Rai without any condition."

(Time Bell rings)

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की कोई तीसरी चिट्ठी आई है क्या ? इस तरह की चिट्ठी का कोई जिक्र नहीं है, केवल दो ही चिट्ठियों का जिक्र है । लेकिन इन दो चिट्ठियों के बाद आगे क्या है :

"Besides the above 32 members of the Assembley have pledged their support to

Shri Rai individually. Out of the 32, 17 have been of doubtful reliability.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Will you please wind up now ? You have taken 22 minutes.

DR. BHAI MAHAVIR : For the opening speaker you have to give some more time. 32 में से 17 मेम्बर ऐसे हैं, जो डाउटफुल रिलायेबिलिटी के हैं। उसके बाद महोदय ने कहा है:—

"Making allowance for the different degrees of reliability, I consider that the total of 171 provides for enough margin to assume comfortable majority."

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कंक्लूजन कैसे निकाला। गवर्नर महोदय ने जो तादाद बतलाई है, उसके हिसाब से बहुमत के लिए 160 सदस्य चाहियें। जो 171 की लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट को देखने के बाद 17 ऐसे हैं जो अनरिलायेबल हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं है। इस तरह से 171 में से आप 17 को निकाल दीजिए, तो 154 बच जाते हैं, इसमें से भी अगर यह कहा जाता है कि जिन 32 आदमियों के बारे में शक है, अगर उनको भी रहने दिया जाय और सिर्फ 17 को ही निकाल दिया जाय तो 319 के हाउस में केवल 154 की मैजारिटी कैसे बन सकती है ? enough margin to assume a comfortable majority. यह जो कम्फरटेबिल मैजारिटी उन्होंने बतलाई है, यह केन्द्र को खुश करने के लिये ही कही गई है ताकि आगे अपने लिये कोई प्रबंध कर लिया जाय। श्री दरोगा प्रसाद राय ने जो दूसरी लिस्ट 14 आदमियों की दी थी, उसको गवर्नर महोदय ने वैरिफाई करने की जरूरत नहीं समझी कि ये 14 आदमी किस की तरफ हैं। शायद उनको इस बात की जरूरत नहीं थी। कहते हैं कि कोई उपेन्द्र वर्मा आये और उन्होंने क्लेम किया कि उनके साथ 175 आदमी हैं They wanted time to submit their list. Governor had no time to give. क्यों टाइम नहीं था। 7 महीने तक जो फैसला नहीं कर सके, जिस चीज को गवर्नर लटकाते आये और फिर उन्होंने ही बिहार में 6 महीने के लिये प्रेजिडेंट रूल बढ़ाने की सिफारिश की, क्या वे उन्हें एक दिन के लिये टाईम नहीं दे सकते थे। श्री उपेन्द्र वर्मा 175 आदमियों की लिस्ट लेकर गवर्नर के पास आये थे, मगर गवर्नर महोदय ने इतना भी कष्ट नहीं किया कि उनकी लिस्ट को देख लेते। यह सब किस लिये हुआ। मेरा निवेदन यह है कि यह इस लिये हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने गवर्नरों को अपने कामों के लिये कठपुतली बना लिया है। केन्द्रीय सरकार ने गवर्नरों से अपना काम निकालने की प्रथा बना ली है और खास कर श्रीमती इन्दिरा गांधी इस तरीके पर चल रही है। सरकार गवर्नरों की प्रतिष्ठा और उनका मान नहीं रखना चाहती है। अभी तक जो घटनाएं हुई हैं, जो इस तरह की बातें देश में हुई, उनसे यह बात सिद्ध हो जाती है।

आज हमारे सामने ऐसे भी उदाहरण हैं कि जो लोग चुनावों में हार जाते हैं, उन्हें गवर्नर बनाया जाता है। मैं श्री पटास्कर का नाम नहीं लेना चाहता हूं; क्योंकि वे दिवंगत हो गये हैं। उनका एक उदाहरण हमारे सामने है और इस तरह से कई और उदाहरण मैं बतला सकता हूं, जहां पर उन व्यक्तियों को गवर्नर नियुक्त किया गया, जो चुनाव में हार गये। अगर सरकार की यह प्रथा जारी रही, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे हमारे देश को हानि ही होने वाली है। तो मैं यह कह रहा था कि हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। श्री खंडूभाई हमारे सामने मौजूद हैं और हमारे सदन में भी एक माननीय सदस्य हैं जिनका नाम मैं शिष्टाचार के अन्तर्गत नहीं लेना चाहता हूं। कुछ लोगों को चुनाव में हारने के बाद गवर्नरों के पदों में सुशोभित किया जाता है और कुछ को रिटायर्ड होने के बाद वाइस चान्सलरों के पदों पर नियुक्त किया जाता है या फिर उन्हें कोई नया एसाइनमेंट दिया जाता है। मुझे इस संबंध में यह निवेदन करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमिशन ने सेन्टर और स्टेट्स के रिलेशन्स के बारे में एक स्टडी टीम नियुक्त करने के बारे में

[Dr. Bhai Mahavir]

कहा था और उसकी रिपोर्ट मेरे सामने है। मैं चाहता था कि उसमें से उद्धरण पढ़, जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नर इस दृष्टि से चुनने चाहिएं कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़े। फिर एक गवर्नर 5 साल की टर्म पूरी करने के बाद कहीं दूसरी जगह भेजा नहीं जाना चाहिए, वह वापस राजनीति में नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार यह हथियार अपने पास रखना चाहती है और गवर्नरों के सामने प्रलोभन की वह गाजर घुमा कर वह मंत्रि-मंडल बनाया जा सकता है, जो श्रीमती इन्दिरा गांधी को मंजूर हो। मैं आज समझ सकता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को इस बात की चिन्ता हो कि वे यहां पर प्रधान मंत्री के आसन पर रहें, जो जवाहर ज्योति दिल्ली में जल रही है, वह खाली तीन मूर्ती भवन में न जले, वह केन्द्रीय सचिवालय में भी जलती रहे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जो प्रधान मंत्री है वह कौन से आदर्शों को, किस तरह के रवैये को लेकर इस देश की राजनीति को किस दिशा में चलाना चाहता है। गवर्नर उत्तर प्रदेश और गवर्नर बिहार ने जिस ढंग से अपने काम को निभाया है, उससे लगता है कि वे केन्द्र के हाथ की कठपुतली बन कर रह गये हैं। इससे केन्द्र की शोभा भी नहीं रही और गवर्नर के पद का भी अपमान हुआ है। इसके लिये कुछ कन्वेन्शन्स बनाने की जरूरत है। गवर्नर्स की कान्फ्रेंस में भी कन्वेन्शन्स बनाने की बात आई थी। उस समय कन्वेन्शन्स नहीं बनाए गए; क्योंकि होम मिनिस्टर ने कहा कि : Situation differs from State to State. सिचुएशन्स डिफर न करें, तो कन्वेन्शन्स की जरूरत ही क्या होगी। कुछ गाइड लाइन्स देने की बात दिसम्बर में गवर्नर्स के सम्मेलन में उठी थी, लेकिन केन्द्र सरकार ने गाइड लाइन्स देने को उचित नहीं समझा। मेरा आक्षेप है कि केन्द्र सरकार ने और विशेषकर गृह-मंत्रालय ने इसलिये गाइड लाइन नहीं बनाई ताकि हर परिस्थिति में नया नुस्खा दिया जा सके और डबल स्टैंडर्ड ही नहीं मल्टीपल स्टैंडर्ड का अधिकार हाथ में रहे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Will you please wind up ? You are raising a new point now.

डा० भाई महावीर : मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। जो कुछ गाइड लाइन्स देनी चाहिए थीं वे नहीं दी गईं। इसलिये गवर्नर के पद का दुरुपयोग—Prostitution of the constitutional processes.—आज की परिस्थिति में हो रहा है। मुझे लगता है कि सदन को चिन्ता करनी पड़ेगी, देश के अन्दर लोकतंत्र को बचाने के लिये, देश की जनता को आगाह करने के लिये और देश की सरकार का चाहे उसके रास्ते में प्रलोभन हो, हाथ पकड़ कर सही दिशा में चलाने के लिये।

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : On a point of clarification. It appears that the Governor in his letter to the President has written in paragraph 5 that the support of the Communist Party of India, the Praja Socialist Party and All India Jharkhand Party is qualitatively more reliable. Exactly what is meant by this "qualitatively more reliable" ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You may ask later. Mr. Sharma.

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं अभी यहां बैठ कर भाई महावीर जी का भाषण सुन रहा था। इस सदन के सामने उन्होंने जो बातें कहीं, वे वकालत के दृष्टिकोण से तो ठीक मालूम हो सकती हैं। लेकिन जहां तक वस्तुस्थिति का सवाल है, जहां तक कि रियलिटी का सवाल है और जिन परिस्थितियों में बिहार के अन्दर राष्ट्रपति शासन समाप्त किया गया और प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की गई, उसके दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। बिहार में क्या हुआ इस सदन के माननीय सदस्यों को अगर यह मालूम हो तो यह बात बिलकुल प्रमाणित हो जायगी कि 1967 के चुनाव के बाद बिहार में जो पालिटिकल इन्स्टेबिलिटी आई उसकी जिम्मेदारी तमाम मुख्तलिफ पार्टियों के ऊपर है, जिनमें भाई महावीर जी की पार्टी

भी एक है। 1967 के चुनाव के बाद वहां एक सरकार बनी, जो एस० वी० डी० की संयुक्त मोर्चे की सरकार थी और उसके मुख्य मंत्री श्री महामाया प्रसद जी थे, जो एक बहुत बड़े प्रवीण वक्ता हैं, बहुत लम्बी चौड़ी तकरीर करते हैं। लेकिन थोड़े ही दिनों के अन्दर लोगों को मालूम हो गया कि उस सरकार में खाली कोरी बातों के सिवा कोई ऐसा दम नहीं था, जो लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। बिहार का पहला दुर्भाग्य तब हुआ, जब एस० वी० डी० सरकार बनी और खत्म हुई और दूसरा दुर्भाग्य तब हुआ जब मिड टर्म इलेक्शन के बाद भी किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ कि वह सरकार बना सके। नतीजा यह हुआ कि पहले कांग्रेस कोलीशन गवर्नमेंट सरदार हरिहर सिंह के नेतृत्व में बना, लेकिन सरदार हरिहर सिंह की गवर्नमेंट गिरी। उसके बाद दस दिनों के लिये श्री भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में सरकार बनी। मुझे हंसी आ रही थी उस बात को सुन कर जब भाई महावीर जी ने कहा कि किस तरह गवर्नर को मालूम हुआ कि कौन-कौन पार्टियां डिपेंडेबिल पार्टियां हो सकती हैं और खास तौर से उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती, इसलिये कि वह किसी दूसरी पार्टी के हाथ में खिलौना नहीं बनना चाहती है...

डा० भाई महावीर : केन्द्रीय सरकार का खिलौना।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं उनकी बात से यह समझा कि उनकी पार्टी दूसरी पार्टियों के हाथ में खिलौना नही बनना चाहती थी।

डा० भाई महावीर : आपने ठीक समझा।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के काम को देखिये खास तौर से जब भोला पासवान शास्त्री की मिनिस्ट्री गिरी। भोला पासवान शास्त्री की मिनिस्ट्री से हमको हमदर्दी नहीं है, पार्टी के नाते और व्यक्ति विशेष के नाते भी। 1967 में और मिड टर्म इलैक्शन के समय बिहार की जनता एक स्थायी सरकार चाहती थी, ऐसी सरकार जो बिहार की उन्नति के कामों को कर सके और बिहार के लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे सके। भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में इनकी पार्टी ने क्या किया। एक संयुक्त सरकार बनी और उसके बाद चुपके से—मैं यह शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्योंकि जब पार्टियां मिलती हैं, तो आपस में मतभेद होता ही है, जब दो-बार पार्टियों का कोलीशन बनेगा, तो उनमें मतभेद होगा—उनकी पार्टी की तरफ से गवर्नर को लिख दिया गया कि जनसंघ अपना समर्थन भोला पासवान शास्त्री की गवर्नमेंट से वापस लेता है। महामाया बाबू के साथ भी इसी तरह से हुआ। 4 बजे के समय उन्होंने असेम्बली में कहा कि हमारी सरकार बिलकुल स्टेबिल गवर्नमेंट है, इसके गिरने का कोई डर नहीं है, लेकिन दो मिनट के बाद सरकार गिरी और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि दोस्तों ने धोखा दिया। इस तरह की दोस्ती में कौन किसका दोस्त है। इसके बाद भी ये समझते हैं कि इनकी पार्टी को डिपेंडेबिल माना जाय तो मुझे उसमें कुछ कहना नही है।

डा० भाई महावीर : भोला पासवान शास्त्री की सरकार कैसे गिरी, इसकी चर्चा करना हो तो मुझे उसमें एतराज नहीं है। मिनिस्टर्स के एपाइन्टमेंट में जो एग्रीड बातें थीं, उनका उल्लंघन किया गया...

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उपसभापति महोदय, मैं तो इस बात को बतला रहा था कि इनकी पार्टी को डिपेंडेबिल क्यो नही माना गया।

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : मालूम होता है गवर्नर ने आपसे पूछ कर ये शब्द लिखे हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महाशय जी, मैंने तो गवर्नर की रिपोर्ट को देखा भी नहीं, ये गवर्नर की रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे और डिपेंडेबिल और अनडिपेंडेबिल पार्टियों की बात कह रहे थे। भोला पासवान शास्त्री की मिनिस्ट्री के गिरने के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद बिहार के अन्दर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी, जो राष्ट्रपति शासन को चाहती थी। सभी पार्टियों ने एकमत से कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उनको खत्म करने की कोशिश सभी ने की। उसके बाद क्या हुआ। सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने भोला पासवान शास्त्री की मिनिस्ट्री के गिरने के बाद बिहार में फिर सरकार बनाने की कोशिश की। यहां पर इस बात की बहुत जोर-जोर से चर्चा की जा रही है कि सरदार हरिहर सिंह ने 186 आदमियों की लिस्ट दी, लेकिन उनकी सरकार नही बनी महीनों तक, लेकिन इसके साथ जब दरोगा प्रसाद राय ने 173 आदमियों की लिस्ट दी, तो (*Interruption*) आपके पास 171 की खबर होगी, मेरे पास तो 173 की सूचना है। (*Interruption*) तो मैं आपसे यह कह रहा था कि दरोगा राय की जो लिस्ट थी, उसको किस तरह से राज्यपाल ने ठीक मान लिया। इसके लिए मैं आपका ध्यान दो तीन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सरदार हरिहर सिंह ने जिस समय राज्यपाल को लिस्ट दी, उस समय क्या स्थिति थी, राज्य में इसे आप देखें। पार्टियों की क्या स्थिति थी? किस तरह से लोग दल बदल रहे थे? इसलिए उस समय एक बड़ा सवाल था और वह यह था कि कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी ने सरदार हरिहर सिंह को सरकार बनाने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन आगे चल कर खास तौर से मैं इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि यह एक दुर्भाग्य की बात थी कि कांग्रेस में स्प्लिट हुआ और जो पुराना पार्लियामेंट्री बोर्ड था, उस ने सरदार हरिहर सिंह को इस तरह की इजाजत दी। लेकिन यह भी सोचने की बात है कि जिस समय सरदार हरिहर सिंह ने यह लिस्ट दी, उस समय हमारी विरोधी पार्टियों के लोग क्या चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि श्री निजलिंगप्पा ने यह कहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर इतने वोट सरदार हरिहर सिंह दिला देंगे तब पार्लियामेंटरी बोर्ड शायद उनको सरकार बनाने की इजाजत देगा। इसकी भी चर्चा और आलोचना उस समय होती थी।

डा० भाई महावीर : यह तो प्रधान मंत्री ने भी किया है। चंडीगढ़ में भी इसी तरह से आपने किया है। (*Interruption*) आपने भी इसी तरह से हमारी बात नहीं सुनी थी, इसलिये हम भी बोलेंगे। आप भी सुनने की आदत डालिये।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : No interruption please, Dr. Mahavir.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA (Bihar) : Dr. Bhai Mahavir, you do not provoke, you do not interfere please.

DR. BHAI MAHAVIR : You also apply the same principle to others. You are interfering.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Order, order.

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : लेकिन इसके बाद कांग्रेस पार्टी में भी स्प्लिट हुआ और यह भी सभी लोगों को मालूम है। उसके बाद क्या हुआ। सरदार हरिहर सिंह पुरानी लकीर के फकीर बने रह कर 186 का नारा बराबर लगाते रहे, जब कि उनकी लिस्ट के 90 आदमियों ने उनको छोड़ कर दरोगा राय को अपना नेता मान लिया। अब आप देखें, 104 आदमियों की पार्टी, जिसमें 90 आदमी उनको अपना नेता न मानें और फिर भी वह नेता गवर्नर के सामने जा कर कहे कि हम नेता है और उसके बाद भी अगर गवर्नर उनकी बात मान ले तो बहुत अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह कि बातें थोथी दलील के अलावा और कुछ नहीं है।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि जिन दो लिस्टों का जिक्र किया गया है । उनके संबंध में जब दरोगा राय ने लिस्ट दी और दूसरी पार्टी के लोगों ने जा कर दावा किया कि 176 हमारी स्ट्रेंथ है, उस समय पोजीशन क्या थी । उस समय पोजीशन यह थी कि सरदार हरिहर सिंह की लिस्ट बिलकुल स्टैंड नहीं करती थी । उन्होंने केवल लिस्ट दी थी, लेकिन आप को यह जान कर आश्चर्य न हो तो खुशी होनी चाहिये कि जो फेरहिस्त हम लोगों ने कांग्रेस की तरफ से दी थी वह व्यक्तिगत आदमियों के दस्तखत ले कर दी थी । वह 40 या 50 आदमियों की लिस्ट नहीं थी ।

श्री पीताम्बर पास (उत्तर प्रदेश) : हम लोगों से आपका क्या मतलब है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : कांग्रेस पार्टी के लीडर श्री दरोगा प्रसाद राय ने जो लिस्ट दी गवर्नर को वह बाजाब्ता लोगों के दस्तखत करा कर दी । वह केवल लिस्ट नहीं थी और उसके बाद, लिस्ट देने के बाद भी राज्यपाल ने जब कहा कि जहां तक स्वतंत्र सदस्यों का सवाल है, उनकी तो यह व्यक्तिगत लिस्ट ठीक है, लेकिन जो रिकग्नाइज्ड पार्टीज हैं, उनके नेताओं का भी समर्थन चाहिये, तो उस समय सी० पी० आई० और पी० एस० पी० के नेताओं ने सिर्फ लिख कर ही नहीं दिया, बल्कि जा कर गवर्नर से कहा कि हम श्री दरोगा राय के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार गठित करना चाहते हैं । उनको हमारा समर्थन है और इसके अलावा स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट्स और झारखंड, होल झारखंड, शोषित दल और बी० के० डी० के लोगों ने इस बात का समर्थन किया और जब गवर्नर इस बात से संतुष्ट हुए और उन्होंने यह समझ लिया कि उनके पीछे बहुमत है, तब उन्होंने श्री दरोगा राय को सरकार बनाने के लिये निमंत्रित किया ।

यहां पर दो चिट्ठियों का जिक्र किया गया । पहली चिट्ठी में उन्होंने दो दिन पहले कहा था कि यहां स्थिति ऐसी है कि जिसमें प्रेसीडेंट रूल ही चलना चाहिये । आप लोगों ने कंप्यूटर की बात कही कि कौनसी ऐसी मशीन थी कि जिससे उन्होंने यह बात जानी । मैं सदन के सामने जो बातें रख रहा हूं, वह किसी कंप्यूटर से ज्यादा कंविंसिंग हो सकती है । इसलिये जब यह सारी चीजें हुई और गवर्नर को फेहरिस्त मिली, पार्टियों का लिखित समर्थन मिला तो उसके बाद दूसरी रिपोर्ट राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजी । यहां पर इस बात की चर्चा की जाती है कि गवर्नर केन्द्र से प्रभावित हो रहे हैं । बार-बार हमारे प्रधान मंत्री का नाम लिया गया, गृह-मंत्री का नाम लिया गया कि उनसे प्रभावित हो कर गवर्नर ने ऐसा किया है । मैं खास तौर से भाई जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि 5, 6 तारीख को मैं उस समय नहीं था, लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि वहाँ पर · · ·

श्री सुन्दर मणि पटेल (उड़ीसा) : रिपोर्ट में जो साथी अनरिलायबिल है, उनके संबंध में क्या कहना है आप को ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उसके संबंध में जिस पार्टी के वे लोग होंगे, वह आपको बतलायेंगे । मैं तो आपसे यह कह रहा था कि गृह-मंत्री पर जो आरोप लगाया जाता है या केन्द्र पर जो आरोप लगाया जाता है कि गवर्नर उनसे प्रभावित हैं · · ·

श्री उपसभापति : आप अपना भाषण जारी रखिये, क्योंकि समय खलास हो रहा है ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं दो या तीन मिनट और लूंगा ।

श्री उपसभापति : एक, दो मिनट में समाप्त कर दीजिए ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : तो मैं उस समय पटना में नहीं था, लेकिन मैंने अखबारों में

[श्री अनन्त प्रसाद शर्मा]

पढ़ा था और उसके बाद सुना कि जिस समय गृह-मंत्री से यह प्रश्न किया कांग्रेस के लोगों ने पटना के अंदर, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं इसके लिये यहां नहीं आया हूं। मैं कन्सलटेटिव कमेटी के लिए आया हूं। जहां तक सरकार बनाने या न बनाने की बात है, यह काम गवर्नर का है और अगर गवर्नर संतुष्ट होंगे, तो सरकार बनायेंगे और अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो नहीं बनायेंगे। अब इससे क्या साबित होता है? अगर मैं किसी विरोधी पार्टी के आदमी से बात करता हूं, तो उसके माने क्या हैं कि उसका कुछ असर एक दूसरे पर पड़ता ही है? अभी हम लोग साथ में गये थे, वहां पर श्री पीताम्बर दास जी से बहुत अच्छी-अच्छी बातें होती थीं ....

श्री पीताम्बर दास : कुछ तजुर्बा अच्छा नहीं रहा "dependability" के बारे में।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : कुछ तजुर्बे अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी होंगे. इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गवर्नर के ऊपर जो दोषारोपण किया जाता है यह ठीक नहीं है। यह भी कहा जाता है कि गवर्नर को कोई गाइड लाइन नहीं दी गयी। तो यह बात हो, इस बात को साबित करती है कि गवर्नर को कोई डेफिनिट इंस्ट्रक्शन्स यहां से वहां दिये जाते हैं कि तुम इस तरह से काम करो और इस तरह से काम न करो और यह खास कर के इसलिये कि the situation varies from State to State, from time to time. तो गवर्नर को पूरी स्वच्छंदता रहती है, आजादी रहती है कि जिस तरह की परिस्थिति हो, उसके अनुसार वह फैसला लें।

इसलिये मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो कुछ हुआ है वह ठीक हुआ है। सभी बातों का पता लगा कर यह सरकार स्थापित करने के लिये मैं उनको दाद देता हूं। आप बिहार के अंदर जाकर देखें कि जब से यह सरकार स्थापित हुई है उसके बाद से लोगों में कितनी खुशी है, उनमें कितनी प्रसन्नता है इस बात पर कि वहां इस प्रकार राष्ट्रपति के शासन का अंत हुआ और एक पापुलर सरकार, एक जनप्रिय सरकार हमारे सूबे में स्थापित हुई।

डा० भाई महावीर : राष्ट्रपति शासन अनपापुलर था?

श्री मोहन लाल गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, जो प्रश्न इस समय सदन के सामने भाई महावीर जी ने उठाया है, वह बहुत महत्व का है और मैं इस में जहां तक गवर्नर का बात का जिक्र है, उसमें ज्यादा महत्व देता हूं, उन कांस्टीट्यूशनल इंप्लीकेशंस को जो इसमें निहित हैं। कांस्टीटयूशनल इंप्लीकेशंस ज्यादा महत्व के हैं बनिस्बत इसके कि गवर्नर ने किसको चीफ मिनिस्टर बना दिया या किस तरह से वह बनाया गया। वह महत्व की बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि उसमें कांस्टीट्यूशनल इंप्लीकेशंस क्या हैं। यह कांस्टीट्यूशनल इंप्लीकेशंस उस समय और महत्व के हो जाते हैं, जब हम यह देखते हैं कि हमारे सबसे बड़े न्यायाधीश, चीफ जस्टिस आफ इंडिया---और वह चीफ जस्टिस ही नहीं हैं, बल्कि अब उनको तजुर्बा इस रिपब्लिक के प्रेसीडेंट की हैसियत में इस एक्जीक्यूटिव के अंदरूनी मामलात का भी हो गया है, तो वह कहते हैं :—

"The Chief Justice, Mr. M. Hidayatullah, today expressed his dismay at the working of parliamentary democracy in India particularly the persistent floor-crossings and change in party alliances and called upon the youth of the country to clean the nation of all bad elements that clog the working of parliamentary democracy."

श्री नेकी राम (हरियाणा) : यह तो आप लोगों पर ही लागू होता है।

श्री मोहन लाल गौतम : हम लोगों पर जरूर लागू होता है, मैं मानता हूं। लेकिन वह लोग जो समझते हैं कि उधर के लोगों पर लागू

नही होता है, वह किस किस्म के इंसान है या देवता हैं या इन्सान से भी गिरे हुये है ?

SHRI A. P. CHATTERJEE : On a point of order. Under article 211 Parliament is not expected to criticise how the judiciary functions and behaves. I think it behoved the head of the judiciary in India also not to make any comment upon how Parliament is functioning. I think the hon'ble Member is not doing a correct thing by quoting from the head of the judiciary from a statement which he made completely without jurisdiction.

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : I am very sorry my friend is wasting the time of the House by raising a point of order. Again he proceeds: —

"....He called upon the youth to be vigilant and 'become guardians of your and your brother citizens' affairs and prevent parliamentary democracy from getting vitiated and sterile".

यह महत्व की चीज है

SHRI AKBAR ALI KHAN : Am I right, Mr. Gautam, that this is not a judgment, but he spoke in some meeting or a conference ?

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : Yes. He spoke this while addressing the 18h Convocation of Saint John's College, Agra.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदश) : अगर जजमेंट होता, तो आप यहां होते ही नही ।

श्री मोहन लाल गौतम : मै कोई जजमेंट नही सुना रहा हूं । यह स्पीच उन्होंने आगरा में डिलीवर की थी, इसलिये वह ज्यादा साफ बोल सके, जजमेंट में कुछ दिक्कतें होती है । और वह शायद इतना साफ न बोल सकते ।

श्री उपसभापति : आपका समय निकल रहा है ।

श्री मोहन लाल गौतम : ये जो इटरप्शंस है, इनको जो 15 मिनट है, उसमें न जोड़ें । उपसभापति महोदय, यह महत्व का सवाल है और इस वक्त यह आपके सामने है । मै विशेष कर उत्तर प्रदेश की बाते ही आपके सामने उस तरह से रखना चाहता हूं, जिस तरह कि यह घटी है । कांग्रेस के विघटन के बाद, कांग्रेस के दो टुकड़े होने के बाद जो कांग्रेस की एक मेजारिटी हाऊस मे थी, वह मेजारिटी किसी कांग्रेस के दल की नही रही लेकिन उसी वक्त गुप्ता साहब के पास बहुत सी पार्टियों के लोग आये और उन्होंने अपनी सपोर्ट प्लेज की और कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप इस्तीफा न दीजियेगा ।

श्री अर्जुन अरोड़ा (उत्तर प्रदेश) : फिर क्यों दे दिया उन्होंने ?

श्री मोहन लाल गौतम : मै जितनी बात कहूंगा वह बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूगा । . .

श्री अर्जुन अरोड़ा : यह बात तो सही है ।

श्री मोहन लाल गौतम : और जो साहब मेरे किसी फैक्ट को चैलेंज करना चाहे मै उनको समझाने के लिये तैयार रहूंगा ।

श्री अर्जुन अरोड़ा : तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, यह तो कहिये ।

श्री एस० डी० मिश्र (उत्तर प्रदेश) : बोलने तो दीजिये ।

श्री मोहन लाल गौतम : इसलिये गुप्ता साहब की उस वक्त मेजारिटी थी तब वह चला रहे थे । इस वक्त चौधरी चरण सिंह और उनकी ओर से, उनके साथियों की तरफ से शुरु होता है यह काम कि भाई हम तुम मिल कर दोनों करेंगे हकूमत तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रदेश का फायद होगा और एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जायेगी । चौधरी चरण सिह ने वक्त-वक्त पर यह बातें कही । करीब तीन महीने हुए यहा इसी सदन के एक साथी के साथ खाना खाते हुए यह राय उन्होंने दी । उन्होंने अपने साथी शिवराज सिह, धर्म सिह, ओम प्रकाश सिह को भेजा कि किसी प्रकार से बातचीत हो जाये और तुरंत हम अच्छी गवर्नमेंट बना

[श्री मोहन लाल गौतम]

सके । उन्होने इस बात को कबूल किया कि इस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिये और इन्होंने अपनी तरफ से पेश किया और प्रोग्राम भी तय हो गया । यह सब चीजें पहले तय हो गई थीं जब कि 10 तारीख को लेटर आफ रेजिगनेशन गुप्ता साहब ने गवर्नर साहब को दिया है । उससे पहले यह सब बातें तय हो गई थी ।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी : (मध्य प्रदेश) : किससे ?

श्री मोहन लाल गौतम : चरण सिंह से और उनके साथियों से । और यही नहीं, जो लेटर आफ रेजिगनेशन गुप्ता साहब ने 10 तारीख को भेजा है उसको चौधरी साहब को दिखलाया गया था, उनकी मंजूरी लेने के बाद भेजा गया था और वह लेटर आफ रेजिनेगशन चौधरी साहब की मंजूरी के बाद हुआ है ।

पंडित भवानी प्रसाद तिवारी : मुझे माफ करेंगे, जो कारसपांडस छपी है गुप्ता जी और चरण सिंह के बीच की उसमें तो यह जाहिर नहीं होता कि कुछ तय हो चुका था ।

श्री मोहन लाल गौतम : जब मैं खत्म कर दूं तब आप मुझसे पूछियेगा ।

श्री उपसभापति : आपका समय खत्म हो रहा है ।

श्री मोहन लाल गौतम : इस तरह से तो मैं नहीं चल सकता, मुझे कुछ समय दीजिये । इस तरह से यह लेटर गया और जो सवाल यहां उठाया गया है, उसके लिये सिर्फ दो बातें मैं कहूंगा । एक तो यह है कि 11 तारीख को पायनियर में, जिसको हमारे डा० भाई ने भी कोट किया है, वहा इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, गुप्ता साहब की तारीफ करते हुए :

"He will not flinch from the responsibility of the Chief Ministership if he is called upon to do so."

इसको आप कहेंगे कि प्रेस का है । अब मैं आपको चौधरी चरण सिंह का लेटर जो कि 11 तारीख का है, वह पढ़ कर सुनाता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि वह क्या कहते हैं :

"My dear Gupta ji,

When Dr. Ram Subhag Singh and Shri Laxmi Ram Acharya saw me in the evening of February 9 I had made it clear to them that there will be no co-ordination committee presiding over the State Government of laying down policies for it. I will say that while I may consult you in regard to the choice of members of Government or laying down policies for it, while I may consult you in regard to the choice of members of government from your party, the decision will rest in my hands."

यह चौधरी चरण सिंह का लेटर है 11 तारीख का, यह उन्होंने 10 तारीख के लेटर आफ रेजिगनेशन को देने के बाद गुप्ता साहब को लिखा जब कि गुप्ता साहब का लेटर उनके पास पहुंच गया है तब ।

इसलिये मैं आपसे अर्ज करूं कि यह चीज बिलकुल पूरी हो चुकी थी और यही नहीं कि यह हो चुका था उसके बाद क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहुंगा, तमाम लोगों ने अखबार पढ़े है, जो आफिशियल कांग्रेस है, उसके अध्यक्ष जगजीवन राम जी गये थे, निराश हो कर आ गये, बहुगुण साहब ने कहा :

"B.K.D. alliance with Gupta group is an unholy alliance."

The C.P.I. said :

"Mr. Charan Singh's alliance with Syndicate is for loaves and fishes of office."

तो ये तमाम चीजे हैं ।

श्री अर्जुन अरोड़ा : जो कोई सिंडीकेट का काम करे वह अनहोली काम करे ···

श्री मोहन लाल गौतम : जो उनकी सिफारिश पर यहां आ जाय और आराम से मेम्बरी करे और रिजाइन न करे वह भी मुबारक है, जो गुप्ता जी की खुशामद कर के हम यहां आये हैं ····

श्री अर्जुन अरोड़ा : आप गुप्ता जी की खुशामद कर के आये है और मै गुप्ता जी के विरोध के बावजूद आया हूं ।

श्री मोहन लाल गौतम : और कुछ कहिये, कम से कम मेरी खुशामद तो की है ।

श्री अर्जुन अरोड़ा : आपकी खुशामद करने को अब भी तैयार हूं, क्योंकि आप बहुत खुबसूरत और सभ्य आदमी है ।

4 P.M.

श्री मोहन लाल गौतम : अच्छा ठीक है । अब 10 तारीख को लेटर आफ रेजिगनेशन दिया है, जो चन्द्रभानु गुप्त जी का है और उस लेटर में मैने आपसे कहा कि वह साफ था । अब सवाल यह है कि जब यह लेटर गया और उन तमाम पार्टियों के दस्तखत भी मौजूद है, उस लेटर की सिपोर्ट में करीब 300 आदमी होते हैं, तो उस वक्त चरण सिंह जी को क्यों नहीं बुलाया जाता है । मैं श्री टी० एन० सिंह साहब और कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी मि० कृष्ण आनन्द रे, हम तीनों 12 तारीख को गवर्नर से मिलते है और उस वक्त हमने कहा यह है लिस्ट, आप बुला क्यों नहीं रहे हैं । उन्होंने कहा कि यह काउंन्टिग आफ हैड्स को लोग पसन्द नहीं करते हैं, श्री सीतलवाड़ साहब और बड़े-बड़े आदमी खिलाफ है । सिगनेचर को मैं पसंद नहीं करता हूं । तो हमने पूछा आप क्या पसंद करते है । कोई रास्ता तो बताइये । उन्होंने कोई रास्ता नहीं बताया । हमने कहा हमको मौका दीजिए, हम मैजारिटी साबित करें । तो हुआ यह कि 17 तारीख की सुबह को मुझे कहा कि आप लिस्ट दे देगे, सिगनेचर्स मैं नहीं चाहता । यह मेरी बातचीत हुई गवर्नर से · · ·

(Time bell rings)

मैंने तो अभी शुरू भी नही किया ।

श्री उपसभापति : आपने 15 मिनट कहे थे । 15 मिनट हो गये ।

श्री मोहन लाल गौतम : गलत बात हो तो आप कहिये । तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हम हैड्स नहीं गिनेंगे और सिगनेचर नही देखेगे उन्होंने मुझे कहा, कृष्ण नन्द राय से कहा कि कांस्टीट्यूशनल पौइन्ट इधर उठे है और जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर है, वह जिसको नामिनेट करेगा वह भी है और हाउस में मैजारिटी तय हो जानी चाहिये । यह था गवर्नर साहब का कहना । यहां तक तो गवर्नर साहब हमारी बात मान गये । उसके बाद 12 तारीख को गवर्नर साहब यहां शाम को आते है और 13 तारीख को चले जाते है । उसके बीच में क्या-क्या होता है वह मै आपसे कहे देता हूं । हमको गवर्नर साहब के बारे में खयाल था कि यह इन्डिपेन्डेट है, बहुत से लोगों का यह खयाल था कि गवर्नर साहब सेन्टर से नाराज है और वह उनको सजा देना चाहते है । यह उनका इम्प्रेशन था, जिसको अगर आप पूछेंगे कहां से लिया तो बता दूगा ।

श्री अर्जुन अरोड़ा : बता दीजिए ।

श्री मोहन लाल गौतम : अभी नही । उनका यहां आना सीक्रेट रखा गया । जब वह यहां आये उस रोज चीफ मिनिस्टर चन्द्रभानु गुप्त ने फोन किया कि क्या बात है । लेकिन उनको कुछ नहीं बताया गया । यू० पी० निवास मे रहे यह सीक्रेट रखा गया । कई दिन तक नही बताया गया, क्यों बुलाया था । उसके बाद कहते हैं कि अपने आप गया था ।

श्री अर्जुन अरोड़ा : खतरा था कि आप कत्ल कर देंगे ।

श्री मोहन लाल गौतम : अब इसी बीच में चक्कर घूमता है । यहां के प्रतिनिधि वहा जाते है । शुरू से ही जाते रहे थे । डी० पी० मिश्र साहब ने वहां पर अपना अड्डा जमा लिया । प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी कपूर साहब के बारे मे कहा जाता है, वह कार्लटन होटल मे थे । 125 रु० रोज ठहरने का है,

[श्री मोहन लाल गौतम]

खाने का अलग होता है और लोग भी वहां थे और मुझ जैसी हैसियत के थे, जो कम-से-कम कार्लटन होटल में ठहरने का खर्च नहीं दे सकते है।

श्री उपसभापति : गौतम जी अब अपना भाषण एक दो मिनट मे खलास कीजिए ।

श्री मोहन लाल गौतम : तीन, चार मिनट लूगा । अब सवाल यह है कि जब गवर्नर साहब यहां आए सेन्टर से बातचीत करने के लिये, तो सेन्टर का दिमाग क्या था । मै थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुप्ता साहब को अपने साथ लेने की कोशिश की थी, अगर वह सफल हो जाता तो वह सब आदमियो से इम्पार्टेंट होते, क्योंकि उनकी फालोइंग सबसे ज्यादा थी, वह नम्बर 2 हो सकते थे, लेकिन उन्होने कहा कि मैं सिद्धांत पर रहूंगा, उनके चीफ मिनिस्टर बने रहने पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ रहने से इन्कार कर दिया, तो उनको खतरा पैदा हुआ । प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने पिछले एक ड़ेढ़ महीने में यू० पी० के पेंतीस चालीस जिलों का दौरा किया है, कोई और स्टेट्स ऐसी नहीं है, जिसमें इतने जिले हों । 35, 40 डिस्ट्रिक्ट्स का दो तीन हफ्ते में दौरा किया ।

श्री अर्जुन अरोड़ा : यू० पी० का नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होने यू० पी० में इतनी दिलचस्पी ली ।

[*Interruptions*]

श्री मोहन लाल गौतम : मै एक मिसाल देना चाहता हूं । प्राइम मिनिस्टर के सामने एक एम०एल०ए० को यह कहा गया—वह दो तीन साहब थे, मै उनका नाम नही कहता—कि 50,000 रु० लो और पार्लियामेंट की सीट लो तुम और इधर आ जाओ । उन्होंने हमसे कहा । हमने बाद में पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि इस-इस तरह से किया जा रहा है ।

श्री अकबर अली खान : नाम बताइये ।

श्री मोहन लाल गौतम : नाम बता दूगा । मेरे पास है ।

श्री एस० डी० मिश्र : अखबारों में आया है ।

श्री मोहन लाल गौतम : तो श्रीमन, मैं कहना चाहता हूं ।

श्री उपसभापति : अत मे कहना चाहता हूं, ऐसा कहिये ।

श्री मोहन लाल गौतम : इसलिये मै कहता हूं कि इस तरह से जो गड़बड़ हुई है, उसका बहुत सीरियस व्हयू है और उसके लिये सबसे ज्यादा यहां पर सेन्टर दोषी है । प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ किया वह बहुत गल्त है । जिस वक्त हम 17 तारीख को · · ·

श्री उपसभापति : अब काफी समय हो गया है ।

श्री मोहन लाल गौतम : 2 मिनट में कहे देता हूं ।

श्री उपसभापति : 20 मिनट हो गये हैं आपके ।

श्री मोहन लाल गौतम : हम लोग बात कर रहे थे गवर्नर से 17 तारीख को । 12 या साढ़े 12 बजे हम लोग थे वहां । उस वक्त गवर्नर के यहां टेलीफोन आता है प्राइम मिनिस्टर का । यह एक साहब ने बताया, जिन्होंने इन्टरसेप्ट किया । मैं पूछना चाहता हूं ओथ हुई 2 बज कर 40 मिनट पर । इस चीज का क्या जस्टिफिकेशन है कि जो आउट-गोइंग चीफ मिनिस्टर हैं उसको सवा 3 बजे तक कोई खबर नहीं लगती है । किसी मिनिस्टर को खबर नहीं दी जाती है । चीफ मिनिस्टर जिसे हैन्ड ओवर करना है, उसको बाद में खबर लगती है और किसी को पता नही लगता ओथ टेकिंग सेरेमनी का । मै दो बातें कहना चाहता हूं ।

श्री उपसभापति : नहीं, अब आपको खत्म करना चाहिये ।

श्री मोहन लाल गौतम : यहां गवर्नर का इम्पीचमेंट नहीं है, इसलिये मैं एक सजेशन देना कि किन-किन आफिसेज के लिये कोई लाइन आफ प्रमोशन नही होना चाहिये । कोई गवर्नर वाइस प्रेजीडेंट न बनाया जाये, उसको एक्सटेंशन न मिले, किसी दूसरी जगह न भेजा जाये । वाइस प्रेजीडेंट को प्रेजीडेंट न बनाया जाये । किसी जज को गवर्नर न बनाया जाये । इसी तरह से तमाम जितने भी टेम्टेशन है, जो एक्जीक्यूटिव के हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के हाथ में वह सब टेम्टेशन देने का रास्ता रोक दिया जाये ।

एक लफ्ज मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से कार्य कर रही हैं, उससे उस पद की, ओहदे की इज्जत घट रही है । उसका नतीजा यह है कि आज ही के अखबार में आया है कि बंगाल में कांग्रेस हार रही है ।

श्री सी० डी० पांडे (उत्तर प्रदेश) : जमानत जब्त हो गई ।

श्री मोहन लाल गौतम : बृशभान जी जो मेरे पुराने दोस्त थे और एक्स मिनिस्टर है, उनकी जमानत जब्त हो गयी । तो उनकी नीतियों का क्या अंत होगा यह सोच लीजिए, समझ लीजिए और आगे अहतियात से बढ़ियेगा ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : There are a large number of speakers who would like to participate in this discussion and, therefore, I would like to request hon. Members to limit their observations to the minimum and no Member should take more than 10 minutes in any case. Mr. Rewati Kant Sinha.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : We can continue it tomorrow. Where is the harm? It is an important matter.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : This is a short duration discussion and we have to abide by the rules. Under the rules I have no right to extend the time. We have to restrict the discussion within 2½ hours.

श्री रेवती कांत सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं सब से पहले आप को यह कह दूं कि यह यू० पी० और बिहार के बारे में जो चर्चा चल रही है, कल जैसा इस सदन मे मांग की गई थी कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की रपट भी वितरित की जाय, जिस तरह से कि बिहार के राज्यपाल की रपट सदस्यों के बीच में वितरित की गई है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के संबंध में राज्यपाल महोदय की रपट को वितरित नहीं किया गया । मैं समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय की रपट वितरित कर दी गई होती, तो आज की बहस में और ज्यादा जान आ गई होती और उसका मतलब ज्यादा हो सकता था । ऐनी हाउ, सबसे पहले मैं बिहार के बारे में कहना चाहता हूं ।

बिहार के राज्यपाल की दो चिट्ठियां, एक जो 11 फरवरी को लिखी गयी थी और दूसरी जो 14 फरवरी को, उन्होंने राष्ट्रपति को लिखी यहां पर सदस्यों में वितरित की गई है । श्रीमन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन दोनो चिट्ठियों को पढ़ने के बाद मुझे अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल महोदय ने अपनी इन चिट्ठियो में बिहार की वास्तविक स्थिति के बारे में वास्तविक नक्शा पेश नही किया है ।

श्रीमन्, मैं बराबर इस मत का रहा हूं और जब कभी पहले इस सदन में बिहार के संबंध में चर्चा चली राष्ट्रपति के शासन के संबंध में, तो मैने बराबर यह कहा कि वहां पर जिस पार्टी के अकेले ज्यादा मेम्बर हों, सिंगिल लार्जेस्ट पार्टी जो हो, उसको सरकार बनाने के लिये बुलाया जाय । उस समय सरदार हरिहर सिंह जी जो संयुक्त कांग्रेस के नेता थे, उनका क्लेम सही भी था, लेकिन कांग्रेस के बट जाने के बाद एक ओर श्री दरोगा राय का दावा है कि उनके पास 84 या 85 सदस्य हैं और दूसरी और सरदार साहब का दावा है

[श्री रेबती कान्त सिंह]

कि उनके साथ 60-65 सदस्य हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाय तो 115 से ज्यादा हो जाता है । इसका मतलब यह हुआ कि ये दो दावे हैं और दावे तथ्य नहीं हो सकते हैं । लेकिन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बिहार विधान सभा में 53 सदस्य हैं और यह एक तथ्य है । इस हिसाब से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी वहां पर सब से बड़ी पार्टी है और राज्यपाल को चाहिये था कि वे उसके नेता को बुलाते ।

श्रीमन्, इसमें उन्होंने शुरू किया है कि 27 जनवरी को श्री दरोगा राय ने एक लिस्ट दी थी, लेकिन 27 जनवरी के पहले यानी करीब 10 रोज पहले, 16,17 जनवरी को, बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी संसोपा की है, उसके नेता श्री रामानन्द तिवारी गवर्नर से मिले । उन्होंने गवर्नर से कहा कि हमारा बहुमत है, इसलिये हमें सरकार बनाने के लिये बुलाया जाना चाहिये । हम को जनसंघ, संगठन कांग्रेस, स्वतंत्र पार्टी, कुछ निर्दलीय मेम्बरों, इस तरह से इन सब लोगों का समर्थन प्राप्त है । लेकिन इस संबंध में राज्यपाल चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात का बिल्कुल जिक्र भी नही किया है । श्रीमन्, उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को श्री दरोगा राय ने 186 आदमियों की लिस्ट दी ही नही, ब्रेकअप फिगर्स दिये और कहा कि इस तरह से 186 आदमी हमारे साथ हैं । जो बात अखबार में आई थी कि राज्यपाल ने 30 जनवरी का आखिरी दिन दिया था कि श्री दरोगा राय 30 जनवरी तक अपने समर्थकों की सूची दस्तखत के साथ दे दें । श्री दरोगा राय 29 जनवरी को दिल्ली चले आए । वे 30 जनवरी को भी वहां वापस नहीं गये और 31 जनवरी को भी वापस नही गये । वे पहली फरवरी को वापस गये । उन्होंने 3 तारीख तक भी कोई लिस्ट नहीं दी । इसलिये इन आल फेयरनेस राज्यपाल का यह कर्त्तव्य था कि जब श्री दरोगा राय ने 30 जनवरी तक अपनी लिस्ट नही दी तो दूसरी बड़ी पार्टी संसोपा की जो थी, उसके नेता को बुलाया जाना चाहिये था । लेकिन गवर्नर महोदय ने इस तरह की कोई बात नहीं की । इसमें वे यह कहते है कि 11 फरवरी को श्री दरोगा राय ने एक लिस्ट दी और उस लिस्ट के पहुंचने से पहले वे अपनी रपट भेज चुके थे जिसमें उन्होंने कहा है कि श्री दरोगा राय ने जो लिस्ट दी है उसमें 10 मेम्बर झारखन्ड पार्टी के और 29 इंडिविजुअल है । उसके बाद गवर्नर महोदय 11 फरवरी को राष्ट्रपति को यह रिकमेंड करते हैं कि ससपेंशन की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया जाय । 11 फरवरी को श्री दरोगा राय अपनी लिस्ट देते हैं और 11 ही फरवरी को गवर्नर महोदय राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं । तो क्या वजह है कि उन्होंने उस दिन श्री दरोगा प्रसाद राय से यह क्यों नहीं कहा कि हम तुम को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और गवर्नर महोदय ने असेम्बली को सशपेंड रखने की सिफारिश क्यों की ।

श्रीमन्, 14 फरवरी को यानी तीन दिन के बाद गवर्नर महोदय फिर रिपोर्ट भेजते है कि श्री दरोगा राय ने जो लिस्ट दी है उसमें क्लेम किया है कि उनके साथ 173 सदस्य है, लेकिन जोड़ने पर वे 171 आते है । गवर्नर ने स्वयं लिखा है कि अगर हम मान लेते हैं कि 171 है लेकिन उसमें से 17 ऐसे हैं जिन्हें रिलायेबल नहीं कहा जा सकता है और जिनकी रिलायबिल्टी डाउटफुल है । वे कहते है कि अगर 17 को छोड़ दिया जाय तो भी 171 की मेजारिटी बन जाती है और यह एनफ मार्जिन है । मै पूछना चाहता हूं कि यह कौनसी अर्थमेटिक है ? अगर 171 में से 17 को निकाल दिया जाय तो सिर्फ 154 ही बचते हैं न ? गवर्नर महोदय ने लिखा है कि 319 के हाउस में दो सीटें खाली हैं । इस समय वहां पर वर्किंग स्ट्रेन्थ 317 की है और इसके लिये वर्केबिल मजारिटी कम से कम 160 होनी चाहिये । लेकिन वे कहते है कि 17 की रिलायेबिल्टी डाउटफुल है और उनको हटाकर कुल 154 बचते है । आगे फिर गवर्नर साहब कहते हैं

कि 14 फरवरी को सरदार साहब ने उन्हें 22 आदमियों की एक लिस्ट दी और उस लिस्ट में 14 ऐसे नाम है जिनके नाम श्री दरोगा राय की लिस्ट में भी है। तो मै यह कहना चाहता हूं कि यह कैसे हो सकता है कि एक ही आदमी एक ही साथ सरदार साहब का भी समर्थन करता हो और श्री दरोगा राय का भी समर्थन करता हो । अगर इन 14 को भी निकाल दिया जाय तो श्री दरोगा राय के साथ, उनके दावे के मुताबिक उनकी कांग्रेस के 85 और 86 सदस्य हैं । उनके दावे में, उनके तथाकथित दावे में, जो तथ्य नही है, सिर्फ दावा है, अगर 14 को निकाल दिया जाय तो फिर सिर्फ 140 उनके साथ रह जाते हैं । लेकिन असेम्बली में वर्किंग मेजारिटी 160 की होनी चाहिये । इस तरह से बिहार के गवर्नर ने स्पष्ट रूप से इस रिपोर्ट के मुताबिक माइनारिटी सरकार को बिहार में स्थापित कर दिया है और ठीक उसी तरह से किया है जिस तरह से शोषित दल की बिन्देश्वरी प्रसाद मन्डल की सरकार को बिहार में बिठलाया था ।

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश के संबंध में कुछ तथ्यपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । मै इस बारे में थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहता हूं और इस बारे में डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं । 10 फरवरी को एक एग्रीमेंट होता है कुछ लोगों के दस्तखत से एग्रीमेंट की एक कापी हमारे पास है । इसमें जो एग्रीमेंट विभिन्न पार्टियों के बीच में हुआ, संगठन कांग्रेस, जनसंघ, संशोपा, इन सब लोगों ने कहा कि हम एक कार्यक्रम के मुताबिक श्री चन्द्रभानु गुप्त का समर्थन करते हैं ।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair]

उन्हीं कार्यक्रमों पर वे नई सरकार को, जिसे चन्द्रभान गुप्त कहेंगे, चाहे उसमें श्री चरणसिंह आये, उसको भी समर्थन देंगे । उसी आधार पर 10 फरवरी को···

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आप के 10 मिनट हो गये है ।

श्री रेवती कान्त सिंह : मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा । श्री गुप्ता 10 फरवरी को जो चिट्ठी गवर्नर को लिखते है उसके एक वाक्य को मै उद्धृत कर देना चाहता हूं ।

"I am confident that on the basis of the same programme the support and confidence of the above parties will be available to the new Government headed by Shri Charan Singh."

लेकिन जब चरण सिंह पब्लिक बयान देते हैं और जब यह पता चल जाता है 14 फरवरी को कि चरण सिंह वह कार्यक्रम लागू नही करेंगे सवा 6 एकड़ के लगान की माफी का और शिक्षकों के वेतन का तो 14 फरवरी को चन्द्रभानु गुप्त गवर्नर को लिखते हैं कि जो हमारे डिपुटी लीडर चौधरी गिरधारी लाल हैं, जो एक हरिजन हैं उनको चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाई जाय । (*Time bell rings*) श्रीमन् समय नहीं है, अन्यथा में कुछ अधिकारियों के कोटेशन्स लाया था, एच० एम० स्टाउट, यू० वांगटे आदि के, जिनमें उन्होंने बतलाया है कि जो आउटगोईंग प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होता है, जो डिफीटेड नहीं हुआ है, अदर रीजन्स से उसने रिजाइन किया है, वह जो चौइस देता है उसको राष्ट्रपति को या गवर्नर को—इंगलैंड में किंग को—बुलाना चाहिये सरकार बनाने के लिये । इस तरह के पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के कन्वेन्शन्स हैं । उन सारे कन्वेन्शन्स की ताक पर रख कर उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने चरण सिंह को सरकार बनाने के लिये बुलाया है । कहा जाता है कि चूंकि चन्द्रभानु गुप्त ने चरण सिंह को गवर्नर को रिकमेंड कर दिया था इसलिये गवर्नर ने बुलाया । यह थोथी दलील है । उन्होंने 10 तारीख को रिकमेंड किया था, 11 को बुला सकते थे, 12 को बुला सकते थे लेकिन मेनोवरिंग हुई और यह मेनोवरिंग दिल्ली में बैठ कर हुई । दिल्ली की मेनोवरिंग ने बिहार और उत्तर प्रदेश के गवर्नर से कांस्टीट्यून का रेप कराया है । इसके लिये मै सरकार की भर्त्सना करता हूं ।

SHRI AWADESHWAR PRASAD SINHA : Mr. Vice-Chairman, it is a grave issue—the conduct of the two Governors in the two States—and our speeches should be suited to the gravity of the situation, and we should realise what we are talking about. The Mover of the Resolution, for whom I have great love, because I respected his father as one of the natioal leaders, has referred to intervention by the Centre. Our esteemed Home Minister went to Bihar in connection with the Advisory Committee. He was there on the 5th and 6th instant and he left on the 7th morning. People talk of telephone talks and coming to Delhi but this gentleman was there and it is the Home Ministry through which the President's Rule is promulgated and through which the President's Rule is withdrawn. So he is the kingpin of the entire thing. He was there on the 5th and 6th and he left on 7th. On the 11th the Governor writes that in his opinion no Government can be formed in the prevailing situation. So it is now crystal clear that the Centre did not interfere in any way with the decision of the Governor. What happened in the meanwhile? I will read the statement of the partyman of Dr. Mahavir in "The Indian Nation" of Patna. It is dated the 16th. On the 15th the General Secretary of the Bihar State Jan Sangh, Mr. Kailashpati Misra said :

"The SVD leaders, including its Chairman Mr. Upendra Verma, who was also the Chairman of the State SSP met the Governor yesterday and staked their claim to form Government on the basis of majority support. But Mr. Tewari and Mr. Thakur went to the Governor later and told him that the SSP was in search of a new SVD and asked for a week's time to enable them to produce their supporters. They did this, though the SSP was already in the SVD".

The paper says :

"Mr. Misra alleged that such 'immoral behaviour had never been witnessed in politics'. He said that if the Assembly was dissolved or if a government was formed by Mr. Daroga Prasad Rai with the support of the CPI the responsibility would lie wholly with these two SSP, leaders."

So he should ask his partyman before he comes here to say who is to blame. It is not the Governor or the Home Minister or others who have been mentioned here. On the 14th they went to the Governor. On the 14th some other important things also happened. Mr. S. A. Dange, the Leader of the Commu- nist Party, Shri Bhupesh Gupta, our esteemed colleague here and others went to Patna. They met the SSP leaders and the PSP leaders and tried to come to some agreement. No agreement was reached and after that, Mr. Dange and Mr. Gupta made a statement. This is the report.

"The two communist leaders in their statement maintained that despite public statements to the contrary by some SSP leaders, the SSP as a party had refused to break from the patently reactionary SVD. This unfortunate fact has left the CPI and other parties no option but allow Mr. Daroga Prasad Rai to form a government if Bihar is to be saved from an indefinite prolongation of Presiden's rule or the formation of a Syndicate-Jansangh led communal and reactionary government."

What Mr. Prem Bhasin has said I will because facts speak more eloquenly than anything else. He said :

"I have no doubt in my mind that a coalition government led by Mr. Daroga Prasad Rai and supported by the PSP without joining it would be stabler than any other government feasible to-day".

So what harm the Governor has done I do not know. The General Secretary or the Jan Sangh has said so, and so also the Communist and the PSP leaders.

Having quoted all this, I will come to Mr. Gautam who was very much interested in the constitutional implications. Article 164 of the Constitution says :

"(1) The Chief Minister shall be appointed by the Governor . . .

(2) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State."

Between the two the Governor has to decide Suppose a Party has a majority in the Assem-

bly, it is not difficult for the Governor but if there are a number of parties what will he do ? The gentleman who spoke previously said that the Governor did not call the largest Party. Our Party had 85 Members. He had to call us. So clause (2) of article 163 comes in and that is about the discretion of the Governor. He has to see which Party commands the majority. Between what he saw on the 11th and what he found on the 14th tere was a difference. These two parties wrote to him pledging their support and that was the reason behind the decision. So there is no question of the Centre interfering in any way with the decision of the Governor. In deciding who should be called in such a situation, the Governor's authority is final and no one can question it. Here it is said :

"The decision of the Governor in his discretion shall be final and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or outht not to have acted in his discreation."

The assembly is being called and it will decide whether Mr. Daroga Prasad Rai has the majority or not and it is being called very soon and the thing will be tested. But do you know what this gentleman, about whose appointment as Chief Minister all sorts of things have been said has done during these few days ? During these few days he has ordered that drinking water shall be made available to the Harijans and scheduled tribe people in all the Villages, within a year!

He has stopped realisation of loans amounting to one thousand rupees from the peasants because of drougut and other conditions, and no interest will be taken for six months. If there is crop after six months, then it will be realised without interest. He has ordered consolidation of holdings wherever a survey has been finalised. He has done other important things. He has asked also for a committee to be appointed to go into the working of sugar mills and see whether they could be nationalised and brought under the control of the Government. So all these good things this genleman has done. Now the former rule, the President's rule, has been removed. All the parties who are today thlking against this popular Governments were talking against President's rule yesterday. Now only because Shri Daroga Prasad Rai has come and their man has not come they are talking like this. Their man could not come because he had no strength behind him greater than that behind Shri Daroga Rai. Of course I have great respect for Sardar Harihar Singh. We were together in the Hazaribagh jail several times since 1930 onwards but, Sir, today he is hardly left with twenty-five persons with him. As four or five M.P.'s are taking a neutral position here, similarly four M.L.A.s are neutral there. Eightyfive are with us, and so how can he form the Government there? That is the point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You may conclude your speech here.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA : All right, Sir. Thank you.

SHRI M. RUTHNASWAMY (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, once more Members of this House have been forced to deplore and denounce the conduct of Governors in regard to the formation of Ministries. They have behaved in a manner not compatible with either the importance or the dignity of their office. In regard to the formation of Ministries, according to the Constitution the Governor is given sole discretion in regard to summoning of the man who is to lead the Council of Ministers. There he is expected to use his judgement, his discretion and his powers of political assessment, and make his decision without any outside advice or interference.

SHRI M. N. KAUL (Nominated) : Question.

SHRI M. RUTHNASWAMY : I am afraid the Governors of Bihar and Uttar Pradesh have acted a dependants of the Central Government. One of them has been acting even as the errand boy of the Prime Minister and the Home Minister. (*Interruptions*) And what is the procedure adopted by the Bihar Governor? In his letter dated February 11, 1970, he says : "Shri Daroga Prasad Rai, leader of one group in the Congress Party, consisting of 79 members, wrote to me a letter"..... and so on and so forth. And after analysing all the sources of support for Mr.

[Shri M. Ruthnaswamy]

Roy he comes to the conclusion : "In my opinion, no Government with any reasonable prospect of stability can be formed now. Therefore, the President's proclamation should be extended for another term of six months." Another sentence runs that because Rajya Sabha elections as coming on, "the Assembly may continue to be in suspension, for the time being". It is a curious word, the word 'suspension' that is used. Is the Legislative Assembly like a piece of dirt which is held in suspension in a glass of water ? But such a work has been used. What he meant was that the Legislative Assembly should be allowed to continue to exist in order to perform this duty of electing Members to the Rajya Sabha. This is his first letter and dated February 11, 1970. Then, within three days he issues another letter dated February 14, 1970 in which he says that he has found that a stable Government is possible. And without any sense of humour he begins this second letter also with the same words and writes "Shri Daroga Prasad Rai met me at 9·00 P.M." on such and such a date "and submitted a list of" representatives. Now how is this list obtained ? By getting signatures from possible supporters of the present Chief Minister, Mr. Daroga Prasad Rai. This process of signature-gathering seems to be one of India's contributions to parliamentary democracy. In other countries the Head of a State assesses the political situation, assesses the respective strengths of political parties, and according to his judgment, according to hs discretion and according to his assessment he calls upon the leader of the party, which he considers to have reasonable prospects, to form the Government, to come and do so. But here we have this process of obtaining signatures from possible supporters of the party. Now what is the worth of these signatures? The signatures are not made before two witnesses, or on oath, or before a judicial officer. Singatures may be repudiated at the time of voting. But this is the procedure that is being followed by our Governors. Let us hope that the Government of Bihar will be as stable as the Governor thinks, but the procedure that he has adopted does not promise any long period of stability. Now let us see how the Governor of Uttar Pradesh behaves. After keeping the Gupta Ministry for three months in power, without summoning the Legislature of the State he suddenly makes up his mind that the Gupta Ministry cannot cammand the confidence of the Legislature. Now, the leader of the Gupta Ministry, Mr. Gupta himself, had the good sense, I suppose sensing the prospect of his continuing in power, to resign and recommend Mr. Charan Singh to be his successor in the Ministy. That quick-change artist, Mr. Charan Singh presumes and requires the support of one group one day, and two or three days after he tries to get the support of another party. And then he is inducted into power. And the Governor of Uttar Pradesh has been specially summoned to Delhi in order to take advice from the Prime Minister or the Home Minister, the Governor, as I said, acting as the errand boy of the Central Ministry. Now, the only office he can go to for advice is the President who appointed him. This kind of acting reducing the dignity and power and self-respect of our Governors should be condemned in no uncertain terms. If the Governor is the Head of his State, then you must give him the scope for exercising his judgment, his discretion and, above all, preserve his dignity and self-respect. Otherwise, the Head of the State would not command that respect and honour, which he should command in the State, among the people of the State, if he is to function as the Governor and the respected Head of his State.

SHRI ARJUN ARORA : Sir, the Governor of U.P. is really an independent person and throughout he has behaved like an independent person. Early in November the split in the Congress Party took place at Delhi and inevitably the split took place at Lucknow. Ten Ministers of the Government of U.P. out of the sixteen resigned and these ten persons and their supporters demanded that the Assembly be called at an early date. The Governor like a constitutional head acted in constitutional propriety and called the Assembly session for the 11th February on the advice of the then Chief Minister, Mr. C. B. Gupta. We, the followers of Mr. Kamalapati Tripathi in U.P.

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh) : Colleagues.

SHRI ARJUN ARORA : I am young; he is older. So I am his follower. You may be his colleague.

We demanded of the Governor, we organised demonstrations, public meetings, issued press statements. We did everything possible but the Governor, Mr. Gopala Reddy, said no. He said as long as Mr. Gupta was the Chief Minister he would accept his advice about the date on which the Assembly was to be called. He did not change the date in spite of widespread massive demand from legislators and from the people of U.P. But there was one significant implication of this. Mr. C. B. Gupta could not face the Assembly in November. Mr. C. B. Gupta could not face the Assembly in December. He could not face the Assembly in January. He had fixed 11th February as the distant date by which time he hoped to manipulate by cajoling or by persuasion, or by some other means, a majority. When on the 31st January it became obvious that Mr. C. B. Gupta had lost support in the Assembly, that Mr. C. B. Gupta had lost support in the Congress Party and when at a meeting convened by Mr. C. B. Gupta to assess his strength only 66 M.L.A's assembled, Mr. Gupta realised where he stood...

SHRI S. D. MISRA : It is all wrong.

SHRI ARJUN ARORA : ... In spite of Mr .S. D. Misra. . .

SHRI S.D. MISRA : I am not contesting anything but you must give correct facts because last time when the party meeting was held...

SHRI ARJUN ARORA : Sir, only 66 persons attended...

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : No interruptions please.

SHI ARJUN ARORA : Only 66 M.L.As were present in the meeting of the Gupta group on the 31st January and the implications were serious. Mr. C. B. Gupta had a nervous breakdown and he is bed-ridden from-that very day. I am sorry about it but he had a nervous breakdown.

SHRI S. D. MISRA : You are saying all wrong things.

SHRI ARJUN ARORA : Friends like Mr. S. D. Misra, Mr. Banarsi Das and Mr. Gautam were misleading Mr. C.B. Gupta; they were misleading the Governor and misleading the whole of U.P.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : No interruptions please.

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIVAN RAM): He had a majority; therefore he resigned.

SHRI ARJUN ARORA : Then when the fateful day . . .

SHRI S. D. MISRA : There is no question of majority or minority.

AN HON. MEMBER : Then why did he resign ?

SHRI ARJUN ARORA : When the fateful day of 11th February came, Mr. Gupta was persuaded by his doctors to resign and do away with the company of Mr. S. D. Misra and others. And he resigned.

SHRI S. D. MISRA : I was not in that company; why do you say that?

SHRI ARJUN ARORA : He resigned on the 10th February just one day before, or rather eleven hours before, the date fixed by Mr. C. B. Gupta himself and accepted by the Governor in absolute constitutional propriety. When that date came Mr. C. B. Gupta was no more Chief Minister, he was hunting for support; no, he was not hunting for support because his doctors would not allow him to take part in politics.

SHRI BHUPESH GUPTA : What do you mean by hunting for support ?

SHRI ARJUN ARORA : I mean supporters. His supporters were hunting for new supporters. After Mr C. B. Gupta had resigned, the Governor did need some time, two, three or four days, to assess the political situation for himself. Mr. Ruthnas

[Shri Arjun Arora]

wamy correctly said that the Governor had to assess the strength of the various groups. He assessed the strength of the various groups and within a week—and it is a short time—he came to the conclusion that 97 members of the BKD and 135 members of the Congress led by Mr. Kamalapati Tripathi who owes allegiance to Mr. Jagjivan Ram, constitute a strength of 232 in a House of 423, and so he called upon Mr. Charan Singh to form the Government.

SHRI B. K. KAUL (Rajasthan) : Why did he come to Delhi then ?

SHRI ARJUN ARORA : He came to Delhi because Delhi is a faseinating place. When he was the Finance Minister of Rajasthan Mr. Kaul also came to Delhi so many times and now that he is no more Finance Minister in Rajasthan he lives here. Delhi is a fascinating place.

SHRI S. D. MISRA : Mr. Arora and Mr. Kaul are here in Delhi as Members of Parliament. They are not here on a pleasure trip.

SHRI ARJUN ARORA : Mr. Kaul was Finance Minster of Rajasthan and not of the Centre. Then also he came to Delhi every month on a pilgrimage or for merry-making, I do not know for what

SHRI B. K. KAUL : You are bracketing me with the Governor of U.P. ?

SHRI A. D. MANI : Sir, on a point of order.

(Interruptions)

SHRI BHUPESH GUPTA : Mr. Gautam is now permanently in Delhi.

SHRI ARJUN ARORA : Mr. Bhupesh Gupta has reminded me of my friend Mr. Mohan Lal Gautam whom I know for 35 years. During the last 20 years Mr. Mohan Lal Gautam has at least half a dozen times opposed Mr. C. B. Gupta and half a dozen times supported Mr. C. B. Gupta.

SHRI A. D. MANI : In twenty years ?

SHRI ARJUN ARORA : Yes, in twenty years.

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, on a point of clarification. Half a dozen times supported, half a dozen times opposed in 20 years. What happens to the rest of the time ?

SHRI ARJUN ARORA : Now Sir, I quote Mr. Mohan Lal Gautam to inform the House of the character of the politics of Mr. C. B. Gupta. I say, character of the politics of Mr. C. B. Gupta because I have nothing personal against him but everything against his politics.

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : May I say something about you also ?

SHRI ARJUN ARORA : You may later on.

On December 25, 1963, Mr. Mohan Lal Gautam told a Press Conference at Lucknow that he had written as General Secretary of the UPCC to Mr. C. B. Gupta to render an account of the donations received and distributed by him during the general election.

SHRI BHUPESH GUPTA: What are you reading from ?

SHRI ARJUN ARORA : I am reading from the National Herald of that date ?

SHRI A. D. MANI : New Age.

SHRI ARJUN ARORA : No, not New Age.

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : What is wrong with it ? What is wrong for a General Secretary writing to a person who has collected money to render the accounts? What is wrong there ? I am not one of those who will excuse that. If they do not render accounts they cannot cotinue in office.

SHRI ARJUN ARORA : That is what I say Sometimes you do not excuse, sometimes you do. And this was not the only Press Conference. Mr. C. B. Gupta did not render accounts in spite of Mr. Gautam having written to him.

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : You cannot say wrong things about me when I am here. Who says he did not ?

SHRI ARJUN ARORA : Mr. Mohan Lal Gautam said he did not. Three days

later on the eve of the New Year, on December 31, 1963, Mr. Gautam held another Press Conference demanding the accounts from Mr. C. B. Gupta. Mr. Gautam is a very clever politician. He will not hold two press conferences for nothing. He will not hold two press conferences demanding accounts which had already been given to him. He should know that.

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : On a point of personal explanation. I was the General Secretary. I was to compile the accounts. I asked for the accounts and Mr. C. B. Gupta was the treasurer and collector of money. These are no press conferences . . .

SHRI ARJUN ARORA : This time should be allowed to me.

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : These are not press conferences only for this purpose. Some press people came. He is quoting something collected by Mr. S. P. Mehra a day or two earlier in the National Herald. That is what he is quoting. He is not quoting the original conference. This is from his friend, Mr. S. P. Mehra, who had written something in the National Herald only two days back.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Please be brief.

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : I will be very brief. If in the House a Member refers to something and misrepresents a Member, he has got every right to explain it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I will give you that right.

(*Interruptions*)

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : Either he cannot refer to a Member sitting here or if he refers to a Member who is sitting here he has got a right to explain his position.

SHRI ARJUN ARORA : He does not have the right to interrupt and begin making another speech. He can give his personal explanation at the end of my speech and not like this.

SHRI BHUPESH GUPTA : He should be given the right to give his personal explanation, but suppose we are not convinced we will ask questions.

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : Yes, certainly.

SHRI ARJUN ARORA : If Mr. Gautam wants the press cuttings of that date in 1963 I can tell him that the file about Mr. C. B. Gupta and about Mr. Gautam is quite complete and I will produce original cuttings from the original newspapers which will be damaging both to Mr. Gupta and his Newfound friend, Mr. Gautam. Now Sir, to come back to the point..

SHRI A. D. MANI : Main point.

SHRI ARJUN ARORA : Thank you for the amendment. The Governor found that Mr. Charan Singh enjoyed the support of 232 in a House of 423. So, he naturally asked Mr. Charan Singh to form the Government. If in-between he came to Delhi, he also came to Kanpur. But he did not seek my advice. Rather I did not render him any advice. So, going to a place does not mean that a person has lost all character and has disowned all responsibility and that he goes out only to take orders. Mr. Gautam goes almost every week or so to Lucknow.I am sure he does not go there to take orders or to take advice. Mr. Charan Singh on becoming the Chief Minister on the 17th of February, did not ask the Governor, like Mr C. B. Gupta, to postpone the Assembly session for two or three months. He said that the Assembly would meet on the 26th. We are discussing this matter today on the 24th. In all fairness to Mr. Charan Singh and the Governor of UP, this discussion should have taken place next week because by that time the Assembly in UP would have met and Mr. Charan Singh would have proved on the floor of the House the fact that he enjoyed the majority support in the UP Assembly and also whether the assessment of the Governor was fair and proper. Then, perhaps there would have been no need for this discussion. Mr. Gautam quoted the Chief Justice of India. Now, Sir, to a lay-man the Chief Justice of India and his name strikes terror.

SHRI A. D. MANI : Respect, not terror.

SHRI ARJUN ARORA : Terror. But all that the Chief Justice of India says is not his verdict. All that the Chief Justice of India says is not the verdict of the Supreme Court. For example, the Chief Justice of India orders food and if he does not like it, he condemns it. That does not become the verdict of the Supreme Court of India.

SHRI M. RUNTHNASWAMY : Who says so ?

SHRI ARJUN ARORA : Mr. Gautam probably does not know the difference between a speech made at a club or a public gathering by the Chief Justice of India and a judgement delivered by him. Sir as you know very well even in a judgement there may be *obiter dicta*. So, the speech of the Chier Justice of India is almost as important as the speech of, say, Mr. Rajnarain or Mr. Mohan Lal Gautam . . .

DR. BHAI MAHAVIR : Or Mr. Arjun Arora.

SHRI ARJUN ARORA : Last but not least Arjun Arora. Secondly, it was a press report, a very brief press report, a cryptic report of a long speech made by the Chief Justice of India. So, we do not know what were the words that he used. In the case of a judgment his words are available, but even in a judgment there may be *obiter dicta*.

SHRI BANKA BEHARY DAS (Orissa) : What is wrong in what he has said ? There is nothing wrong in what he has quoted.

(Time bell rings)

SHRI ARJUN ARORA : I was interrupted by Mr. Gautam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I have given you time for interruptions also.

SHRI ARJUN ARORA : I will wind up. As a citizen of UP, who was born in UP, educated in UP, brought up in UP, worked in UP and who represents UP in this Rajya Sabha—perhaps not very ably—I am very grateful to Governor B. Gopala Reddi for bringing to an end the corrupt rule of Mr. C. B. Gupta. All the politics of Mr. C. B. Gupta are based on political corruption, are based on money power—. . .

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : That is what is happening here at the Centre.

SHRI ARJUN ARORA : It is based on manipulations . . .

SHRI DAHYABAHI V. PATEL : Is it any different in the Centre ?

SHRI ARJUN ARORA : It is based on dirty manipulations. When I say that as a citizen of UP, I am grateful to Mr. Gopala Reddi for bringing that corrupt rule to an end. I represent eighty million people who are citizens of UP who work in UP and who belong to this country.

Before I sit down I must say a word on a matter of personal explanation. Mr. Mohan Lal Gautam said that I came to this House by 'Khushamed Karowing'. I have seen Mr. Gautam 'Khashamad Karowing' people for jobs to his sons and sons-in-law. but I do not want to go into it.

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : On a personal explanation. . .

SHRI S. N. MISRA : Do you allow such things ? I do not know. He should not have been allowed.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I have allowed him.

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : The way in which Mr. Arjun Arora has attacked me is the way of Kunjaras, Bhangis and the low class people. Therefore, I am not going into all these details. मेरा कोई आदमी नहीं है जो नौकरी के लिये गया हो, मेरा कोई लड़का नही है जिसके लिये नौकरी मांगने गया हूं । और अर्जुन अरोड़ा साहब किस लिए कहां-कहाँ गये हैं, अगर वह कहेंगे, तो मैं खोल दूगा क्या हुआ है ।

श्री अर्जुन अरोड़ा : आप सब खोल सकते हैं । मैं आपको चुनौती दे सकता हूं । आप मेरे पर खुशामद करने के लिये नौकरी दिलवाने के लिये आये हैं । मेरे सामने आपने खुशामद की थी एक गवर्नमेंट आफिसर की जो मेरे पास टिका हुआ था ।

श्री मोहन लाल गौतम : मैंने कोई खुशामद किसी गवर्नमेंट आफिसर की नहीं की । मैं उन आदमियों में हूं जो अपने पिछले 50 सालों

5 P. M.

में अपनी लाइफ को बहुत पवित्र रखे रहा है।

मैंने श्री जवाहर लाल के सामने सिर नहीं झुकाया और उन्होंने मुझे अपने साथ रखने की कोशिश की। मैंने सरदार पटेल के सामने सिर नहीं झुकाया, मैंने मौलाना आजाद के सामने सिर नही झुकाया, और न ही मैंने श्री गुप्ता के सामने सिर झुकाया है। जो ठीक बात होती थी मैं उसके साथ होता था। आज मैं किसी का भक्त नहीं हूं मैं पालिसी के साथ हूं और किसी का गुलाम नहीं हूं। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री गुप्ता ने पूरा हिसाब दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में कायदे से एक छोटी सी कमेटी बना दी गई थी। जो हर तरह का हिसाब रखती है जो कि खर्च होता है। श्री गुप्ता जी के पास एक-एक पाई का हिसाब है जो पिछले 20 या 25 सालों से इस संबंध में खर्च किया गया है। अगर चार आने के दही बड़े भी खाये गये हों तो उसका हिसाब रखा गया है। इस तरह का हिसाब हमारे पास है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह का हिसाब हमारे पास है उस तरह का हिसाब किसी के पास नही होगा। गुप्ता जी के पास इस खर्चे का पूरा हिसाब है और जब कभी उन्हें कहीं से हिसाब नहीं मिलता है तो वे फौरन हिसाब भेजने के लिये कहते हैं।

(*Interruptions*)

श्री अर्जुन अरोड़ा : रिमाइन्डर भेजने के लिए प्रेस कांफ्रेंस की जरूरत नही है।

(*Interruptions*)

श्री मोहन लाल गौतम : रिमाइन्डर के लिए हमने चिट्ठी भेजी थी। (*Interruptions*) तो मैं यह कह रहा था कि मैंने श्री जवाहर लाल नेहरू के सामने सिर नही झुकाया, मैंने सरदार पटेल, मौलाना आजाद, श्री पंत और न ही श्री चन्द्रभानु गुप्त के सामने सिर झुकाया। (*Time bell rings*) श्रीमन् मैं अपना सिद्धांत रखता हूं और मेरा आचरण बिल्कुल पवित्र है। मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूं। श्री गुप्त जी की जो ठीक पालिसी थीं और हैं मैं उनके साथ हूं और आज भी जो उनकी पालिसियां हैं मैं उनके साथ हूं। हम लोगों का दामन साफ है और जो भी कोई हिसाब जानना चाहता है वह उसको दिखा सकता हूं। श्री गुप्त जैसे आदमी आपको बहुत कम मिलेंगे।

SHRI BHUPESH GUPTA : Mr. Vice-Chairman, you gave him the permission. He was right in demanding it.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : You have given permission for what?

SHRI BHUPESH GUPTA : For personal explanation for Mr. Gautam.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : How can you give explanation? Sit down.

SHRI BHUPESH GUPTA : I would like to ask him one thing.

SOME HON. MEMBERS : No, no.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Mr. Man Singh Varma.

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : What is the order of rotation? We do not understand.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I thought from Jan Sangh he is the first speaker. All right, I have called him now. I should have called the other party.

श्री मान सिंह वर्मा : उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम आज यहां पर एक गम्भीर विषय पर बात चीत कर रहे हैं मगर इस बहस में जो समय का अच्छा उपयोग होना चाहिए उसको हम आपस की लड़ाई में ही सर्फ कर दे रहे है। हम इस सदन का समय आपस के झगड़ों में और एक दूसरे की बुराई करने में लगा रहे हैं और इस तरह से इस सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कम से कम इस प्रकार से आपस में एक-दूसरे की बुराई न करें और समय को बरबाद होने से बचाने की कृपा करें।

श्रीमन्, आज इस सदन में जो चर्चा हो रही है उसमें गवर्नरों के कार्यों की चर्चा हो

[श्री मान सिंह वर्मा]

रही है। मैं समझता हूं कि जिस समय संविधान बना था, उस समय संविधान बनाने वालों ने इस पद को इस वास्ते रखा था कि अगर जनतंत्र के लिए किसी प्रकार का संकट आये, तो उस संकट का सामना करने के लिए, बिगड़ती हुई स्थिति को सम्भालने के लिए ही इस पद का प्रयोग किया जाय। परन्तु मेरा अनुभव यह है कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदयों ने काम किया है उसकी वजह से उन पर से विश्वास समाप्त होता चला जा रहा है। मैं समझता हूं कि शायद मूलतः और मौलिक रूप से यह गलती हुई है कि प्रजातंत्रीय ढंग से जो सरकारें बनती हैं उनकी बिगड़ी हुई परिस्थिति को टीक करने के लिए एक ऐसा आदमी अपवाईट किया जाता है जो किसी के द्वारा नियुक्त होता है।

श्रीमन्, यह एक सामान्य तरीका है कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वह हमेशा उसके प्रति वफादार होता है जो उसको नियुक्त करता है। यह एक स्वाभाविक बात है और आज तक होता चला आ रहा है। गवर्नर जो नियुक्त किये जाते हैं वे यह देख कर नियुक्त किये जाते हैं कि कौन-सा राज्यपाल ऐसा होगा, कौन-सा ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे इन्टरेस्ट को वहां पर रहकर सेफगार्ड कर सके। इस तरह की बात हमने देखी है और इस बात को देखकर गवर्नरों की नियुक्ति की जाती है कि कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जो नियुक्त करने वाली सरकार का समर्थन करेगा।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन हमारे देश मे ज्यूडिशरी ने यह साबित कर दिया है कि उन लोगों की जो नियुक्ति होती है उसमें वे किसी के प्रेशर में नही होते हैं, किसी के दबाव में नही रहते हैं। आज हमारे देश के लिए यह गौरव की बात है कि संसार के अन्दर हमारी ज्युडिशरी की बहुत प्रसिद्धि है और हमारी ज्युडिशरी ने इस संबंध में समय-समय पर उदाहरण भी पेश किये है। परन्तु इसके साथ ही साथ यह एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम यह देख रहे है कि हमारी ज्युडिशरी के ऊपर हमला किया जा रहा है। किस वजह से हमला किया जा रहा है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपालों का पद जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, जिन कारणों से इस पद का निर्माण किया गया था, उनका दुरुपयोग किया गया है। आखिर यह देखा जाना चाहिये कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो परिस्थिति सामने आई वह हुई क्यों।

आप यह जानते है और इस बात को झुठलाया भी नही जा सकता कि जब से प्रेजिडेंट का इलैक्शन हुआ है तब से यह स्थिति हमारे सामने गम्भीर रूप से सामने आई है। सब लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के कारणों से कांग्रेस में दो गुट हो गये हैं। रूलिंग गुट, जो राज्य कर रहा है, उस दल ने अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए स्थान-स्थान पर प्रत्येक प्रदेश में इस बात की कोशिश की कि हमारे दल का वहां पर बहुमत हो जाय। जो सरकार हम से मिलकर नही चल रही है, जो सरकार हमारे मन की नहीं है, उस सरकार को वहां पर विगाड़ा जाय और अपनी मन पसन्द की सरकार वहां पर बनाई जाय। इस बात को सब मानेंगे कि क्या इस तरह की कोशिश केन्द्र की ओर से नही हुई? केन्द्र में जब कांग्रेस के दो गुट हो गये तो उसका प्रभाव सारे देश में पड़ा और सारे प्रदेशों में दो गुट हो गये। जिन प्रदेशों से सत्तारूढ़ गुट की सरकारे नही थी वहां पर इस बात का प्रयत्न किया जाने लगा कि वहां की सरकार को उखाड़ा जाय और अपनी मन पसन्द सरकार वहां पर बनाई जाय। यही एक मूल कारण है जिसकी वजह से आज हमें इस तरह की बात देखने को मिल रही है।

जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश में श्री चन्द्रभान गप्त

की सरकार थी। वहां पर भी कांग्रेस में दो गुट हो गये। एक चन्द्रभान गुप्त का गुट हो गया और दूसरा श्री त्रिपाठी का गुट हो गया। पहले तो इस बात की कोशिश होती रही कि श्री चन्द्रभान गुप्त केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर चलें जैसा केन्द्र चाहे वैसा श्री गुप्त करें। लेकिन श्री गुप्त ने इस तरह से चलने से इन्कार कर दिया। पहले तो केन्द्रीय सरकार को ऐसा लगा कि वे उनकी लाइन पर चलने लगे हैं मगर बाद में जब उन्होंने साफ इन्कार कर दिया तो केन्द्र की सरकार घबराई। श्री गुप्त ने कहा कि मैं रबड़ की मुहर बन कर नहीं रह सकता हूं। केन्द्र की ओर से इस बात के संकेत दिये गये कि अगर हमारा मनमाना चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो तुम को रहने नहीं दिया जायेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : अब आप खत्म कीजिये क्योंकि आपकी पार्टी का एक आदमी पहले ही बोल चुका है और आप 7 मिनट बोल चुके हैं।

श्री मानसिंह वर्मा : हमारी पार्टी के दो नाम हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : अभी दूसरी पार्टियों के पहले आदमी भी नहीं बोले।

श्री मानसिंह वर्मा : आप मुझे थोड़ा टाइम और दीजिये, मैं उसके बाद समाप्त कर दूंगा। तो उस समय इस बात का प्रयत्न किया गया---और इसको कोई झुठला नहीं सकता---माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक जिले में जा जाकर इस बात का प्रयत्न किया कि गुप्त जी कि सरकार को तोड़ा जाय। इस प्रकार प्रजातंत्र रह सकता है? प्रजातंत्र किस प्रकार रहेगा जब प्रधान मंत्री इस बात का प्रयत्न करे कि फलां सरकार को तोड़ा जाय, फलां सरकार को बनाया जाय। मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति जब तक प्रधान मंत्री नहीं बनता है तब तक वह किसी पार्टी का रहता है लेकिन प्रधान मंत्री बनने के पश्चात् वह सारे देश का प्रधान मंत्री रहता है और उसे इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जो सरकार चल रही है उनको सपोर्ट दिया जाय, बल दिया जाय और उनको अच्छी प्रकार से चलाने का प्रयत्न किया जाय। इसके बजाय चलती हुई सरकार को रोडा बन कर तोड़ने का प्रयत्न किया गया और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि चन्द्रभान गुप्त को रिजाइन करना पड़ा। गवर्नर ने भी इस बात के लिए प्रयत्न किया कि प्रधानमंत्री जैसी चाहें वैसी परिस्थितियां पैदा की जायं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं रेड्डी साहब से कि जिस समय गुप्त जी ने रिजाइन किया और रिजाइन करने के पश्चात् यह कहा कि चौधरी चरण सिंह को बुलाया जाय उस समय जो फिगर दी गई थी वह 295 व्यक्तियों की दी गई थी, उस समय तीन दिन तक उनको क्यों नहीं बुलाया गया? इसका जवाब आज तक न उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया और न कहीं और से किसी प्रकार का उत्तर आ रहा है। जब चरण सिंह मिल गए और उन्होंने कहा कि मेरे साथ 132-134 आदमी हैं तो एकदम फौरन ही नाटकीय ढंग से उनको बुला लिया जाता है। इसका क्या अर्थ है? क्या यह इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वहां का गवर्नर वही चीज करना चाहता था जो इन्दिरा गांधी चाहती थीं। (*Time bell rings*) कहना तो बहुत कुछ था लेकिन आपकी आज्ञा मानना आवश्यक है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आज तक जो राज्यपालों का रोल रहा है अपने देश के अन्दर उसको देखते हुए राज्यपाल का पद रखा जाय या खत्म कर दिया जाय यह प्रश्न हमारे सामने है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की पद्धति चल रही है उसमें राज्यपाल का जो पद है वह डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, अभी कई माननीय सदस्यों ने बोलते हुए यह कहने की कोशिश की कि बिहार और

[श्री सूरज प्रसाद]

यू० पी० में जो सरकारें बनी हैं उन सरकारों के बनने से जनतंत्र की हत्या हो गई है । किसी ने यह भी कहने की कोशिश की कि बहुमत कही और था और सरकार कहीं और बनी और इस तरह से जो सरकारें बिहार और यू० पी० की बनी है वे अल्पमत की सरकारें हैं और इस तरह की सरकारों को बना कर हिन्दुस्तान के अन्दर एक गलत राजनीतिक परम्परा कायम करने की कोशिश हो रही है । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि बिहार में जो सरकार बनाने के बारे में हमारे भाई महावीर जी बोल रहे थे वह सरकार बनती तो उसमें कौन-कौन लोग होते । वे दरोगा राय की सरकार से सहमत नहीं हैं । वे सरकार बनाना चाहते थे हरिहर सिंह के नेतृत्व में । श्री हरिहर सिंह, सिंडीकेट पार्टी के सदस्य है । बिहार में सिंडीकेट पार्टी में अइयर कमीशन के तमाम अभियुक्त हैं । उस पार्टी के अन्दर श्री कृष्ण बल्लभ सहाय हैं, उस पार्टी के अन्दर सत्येन्द्र नारायण सिंह हैं, उस पार्टी के अन्दर अम्बिका शरण सिंह हैं, उस पार्टी के अन्दर महेश प्रसाद सिंह हैं ।

ये बिहार के वे सूरमा है जिनके ऊपर करप्शन का बहुत बड़ा चार्ज लगा हुआ है । सबको मालूम है कि कृष्ण बल्लभ सहाय ने अपने मुख्य-मंत्रित्व काल में चाहा था कि बिहार के तमाम धन को अपने बेटों को दे दें, महेश प्रसाद सिंह ने चाहा था कि अपने राज्य काल में तमाम धन...

श्री एस० डी० मिश्र : राम लखन यादव कहां हैं?

श्री सूरज प्रसाद : आप इन लोगों को तो निकालने का प्रयत्न कीजिए । अभी सिंडीकेट कांग्रेस में बिहार में तमाम भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं और ऐसे लोगों को मिला कर बिहार के अन्दर सरकार बनाने का प्रयत्न हो रहा है । इसी सरकार के अन्दर श्री कामाख्या नारायण सिंह रहने वाले थे जिन पर बिहार के धन और जंगल की लूट का आरोप लगा हुआ है । जनतंत्र की रक्षा की बात कहीं गई । आप जनतंत्र की रक्षा के लिए यह हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे । ये लोग ऐसी हुकूमत बनाना चाहते थे जो बिहार के अन्दर भ्रष्टाचार की ऐसी मिसाल पैदा करे जो बिहार के इतिहास में अमर रहे । यह जनतंत्र के हिफाजत की बात नहीं थीं । मेरे दाहिने बाजू जो लोग बैठे हुए हैं वे बिहार के अन्दर ऐसी हकूमत देखना चाहते थे जो वहां घिनौना राज्य स्थापित करती । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वहां जनतंत्र की हत्या की बात नही है । सिन्डीकेट पार्टी के लोगों ने बिहार के माथे पर कलंक का टीका लगाया है और दूसरा कलंक का टीका लगाने की कोशिश हो रही थी जिसे जनता ने परास्त कर दिया, चकनाचूर कर दिया ।

बिहार में सिर्फ सरदार हरिहर सिंह कोशिश नहीं कर रहे । बिहार में दूसरे सूरमा थे रामानन्द तिवारी । उन्होंने खुद कहा कि मैं संविदा का नेता नही हूं । इसकी पुष्टि कर्पूरी ठाकुर ने भी की । हमारे साथी सोशलिस्ट पार्टी के कह रहे थे कि संविद बनी थी जिसके अन्दर सोशलिस्ट पार्टी थी, जनसंघ के लोग थे, स्वतंत्र पार्टी के लोग थे, दूसरी पार्टियां थीं और इसके नेता थे रामानन्द तिवारी । ऐसी कोई भी संविद बिहार में नहीं बनीं । बुलाया किसको जाता । उनका घोड़ा ही पहगा छुड़ा कर भाग गया ।

कुछ लोगो ने कहा कि यह सरकार अल्पमत की सरकार है । मैं कहना चाहता हूं कि जब केरल में हुकूमत बनी थी तो उस समय भी इन पार्टियों में चिल्लपो की थी । आज केरल के अन्दर इस बात की पुष्टि हो गई है कि केरल की हुकूमत अल्प मत की हकूमत है या बहुमत की हुकूमत है । बिहार के अन्दर जो हुकूमत बनी है उसका फैसला गवर्नर हाउस में नहीं होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, लोकसभा में नहीं होगा, उसका फैसला बिहार असेम्बली में होगा । बिहार की असेम्बली की बैठक होने

दीजिए, फैसला हो जायगा कि बिहार के अन्दर बहुमत दरोगा राय का है या माननीय श्री 108 हरिहर सिंह का । इसका फैसला हो जायगा, घबड़ाने की जरूरत नहीं है । मेरा यह विश्वास है कि बिहार की जो हुकूमत बनी है उसके पीछे बहुमत है और बहुमत रहेगा

[THE DEPTY CHAIRMAN IN THE CHAIR]

जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत ही सोच समझ कर बिहार की हुकूमत का साथ दिया है, इस बुनियाद पर कि एक 35 सूत्री कार्यक्रम है । मैं कहना चाहता हूं कि दरोगा राय की हुकूमत 35 सूत्री कार्यक्रम का पालन करती रही तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन हासिल होगा । अगर दरोगा राय की हुकूमत 35 सूत्री कार्यक्रम का पालन नहीं करती तो कम्युनिस्ट पार्टी राइट-एबाउट-टर्न हो जायगी और कभी उस तरह की सरकार में शामिल नहीं होगी ।

गवर्नर के बारे में इस तरह के आरोप वाली बातें गलत हैं । कोई यह कहता कि गवर्नर का पद रहे या न रहे, इस पर कुछ बहस होती तो बात अलग थी । मैं यह मान सकता हूं कि गवर्नर का पद अजनतांत्रिक पद है, वह जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता । किसी अजनतांत्रिक चीज में जनतंत्र को खोजना उसी तरह से मुश्किल है जैसे दिन के अन्दर चन्द्रमा को या तारों को खोजना । इस लिए उस पद को अगर हटाने की बात की जाय, उठाने की बात की जाय तो मैं उस का समर्थन कर सकता हूं । मैं कहूंगा सेंडीकेट के लोगों से, जनसंघ के लोगों से और मैं कहूंगा दूसरी पार्टियों के लोगों से कि सचमुच में अगर जनतंत्र की हिमायत आप करना चाहते हैं तो मांग कीजिए कि गवर्नर का पद उठा दिया जाय और इस के लिए कम्युनिस्ट पार्टी आप को समर्थन दे सकती है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Niren Ghosh. Try to be brief.

SHRI NIREN GHOSH : Sir, I have waited so long because I thought I would offer some remarks on this occasion because the debate demands some observations from our party; otherwise I would not have spoken.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Some, not many.

SHRI NIREN GHOSH : Is it a new discovery for that side or for these benches that Governors have all along acted as an instrument of the Central power? Just remember 1952 when in Madras the Congress was in a minority and the Governor from the oblivion brought Shri Chakravarty Rajagopalachari who was not even a Member of either House and made him the Chief Minister. That did not trouble their conscience. Again, in P.E.P.S.U. there was Akali majority, yet somehow or the other the minority Congress Government was installed by the Rajapramukh. That also did not come under fire.

SHRI M. N. KAUL : There is a precedent for every action of the Governor.

SHRI NIREN GHOSH : You were then the Secretary of one of the Houses here. You should remember all that happened.

Then, again, in 1959 under the august leadership of Pt. Jawaharlal Nehru a Government enjoying a majority in Kerala was thrown out and then there was the spectacle of a minority Government of notorious Shri Pattom Thanu Pillai being installed in power, supported by Congress. Then nobody thought about it. Now after twenty years of blissful slumber like Rip Wan Winkle our friends on these benches have woken up to the danger because now it is their State Government which is under fire. I am glad you have at least woken up to the reality.

SHRI M. V. BHADRAM (Andhra Pradesh) : But it is too late.

SHRI NIREN GHOSH : This is the thing which is happening in the country. Had Shri Arjun Arora been here I would have asked him and I ask these benches also whether it was not a minority Government when it was installed in Kerala.

HON. MEMBERS : No, no.

SHRI NIREN GHOSH : It was a minority Government. How is it that in supporting that minority Government the kingpins of the Congress combined together.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa) : Common danger.

SHRI NIREN GHOSH : I dare say the peoples of India will not forget to draw appropriate lessons from those manoeuvrings and politiking.

SHRI M. N. KAUL : They will forget everything. Of course, historians will recall.

SHRI NIREN GHOSH : Why should the people forget? These are realities because many governments would be toppled and this question will come up again and again. It will continue to be a live issue and Parliament will debate it and the people will judge all the parties in this contest. At that time nobody raised that issue here when this story was repeated in Kerala. But now they have been stirred. I want to put my finger on this aspect of the thing. Let my countrymen judge which party behaves in what way and how each party behaved in a particular political context. It is also revealing with regard to the two Congress parties how horse-trading is going on, on the floor of the two Houses. It is good for the country. The truth is coming out. The whole thing will come out. Something at least will go into the press if they catch it. If the eyes of the friends sitting in the press gallery are just not blurred, at least something will go to the people and they will come to know of it and that will be good for the country.

Then in 1967 the West Bengal Ministry was toppled. I raised my lone voice in this House. Then my friends on those benches also supported us. Almost single-handed I fought against our venerable Home Minister, Shri Y. B. Chavan. The entire House shouted against me. Now Dr. Bhai Mahavir has chosen to remember that affair. It is good. But in the event of doing so he had a dig at the Ministry functioning there pleading for Central interference in West Bengal. Thereby he has scuttled own Resolution. If he has done so I cannot help it. It is for them to decide.

That being the state of affairs in India, Centre-State relations are intimately involved in it. Today Mr. Charan Singh is the Chief Minister. Tomorrow somebody else will be the Chief Minister because horse-trading is going on. Nobody knows as to how many hands the Chief Ministership will change because there are no policies involved. In all these groupings that have come no policies and programmes are involved. Only personal groups and parties are there forming those combinations in order to aspire to come to the seat of power.

SHRI M. N. KAUL : Make hay while the sun shines.

SHRI NIREN GHOSH : No programmatic things are involved but this vital principle is involved. In the process you forget one fact that you are provoking all the States of India one after another. You are striking at the fabric of federal India. Unless you give up this policy of utilising the Governors as the instrument of Central power, this India will be torn as under. That is a serious thing which I should like the Central Government to remember. Therefore, you cannot provoke all the States' peoples. Therefore, you should agree that the Governor's post should be abolished. Why not pass a resolution? If these benches bring a resolution to that effect we will support it and in the present context it will be passed by the Houses. Let us have it. Or pass a resolution that the Governors must behave just as the British Crown behaves. There are enough precedents, written and unwritten. Let Parliament pass a resolution to that effect...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You will finish now.

SHRI NIREN GHOSH :... and in the present conditions they will be voted and passed.

SHRI S. D. MISRA : You can bring it.

SHRI NIREN GHOSH : That is for Parliament. The Parliament should not lay down merely guidelines that can be interpreted in any way you like. But there is one thing. Either abolish the office of the Governor or the Governor must behave as the Crown in England behaves, A to Z

in letter and in spirit. That is the only remedy about the existing state of affiairs; otherwise it is a serious thing which is eating into the vitals of the body politic of India. Beware of the looming danger which is threatening you.

SHRI BHUPESH GUPTA : My f iend here is asking me whether I will support the abolition of the Governor's post.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Do not worry about it.

SHRI S. D. MISRA : Please do bring a resolution, Mr. Gupta.

SHRI BHUPESH GUPTA : I can bring it any day provided you will support it. Let us discuss the subject. There is no question about it. The Governor's post should be abolished.

श्री पृथ्वीनाथ (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश की समस्या पर जो विचार यहां हो रहा है उसके सम्बन्ध में मुझे यह अर्ज करना है कि उसके तीन पहलू हैं जिनके ऊपर अगर हम अपने विचार को सीमित रखें तो किसी निश्चय पर पहुंच सकेंगे ।

पहली समस्या है कि गवर्नर महोदय ने जो कुछ किया है उसमें भारतवर्ष की सरकार का कितना हाथ है और कितना हाथ नहीं है । जो कुछ गवर्नर, उत्तर प्रदेश, के सम्बन्ध में कहा गया उसमें केवल तीन बातें ऐसी कही गई हैं जिनसे यह प्रतीत होता है, जिनमें यह एलिगेशन लगाया जाता है कि गवर्नर महोदय ने जो कुछ किया वह भारत सरकार के इशारे पर किया । एक तो "स्टेट्समैन" अखबार के न्यूज आइटम को दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि गवर्नर महोदय को दिल्ली बुलाया गया था । मेरे साथी शायद भूल गये कि उसी रोज गवर्नर महोदय ने उस बात का डिनायल कर दिया था कि मैं जो दिल्ली जा रहा हूं, वह अपने किसी और कार्य से जा रहा हूं, मुझको बुलाया नहीं गया है । गवर्नर महोदय के उस डिनायल के बाद उसका उल्लेख करना कहां तक उचित है यह सोचने की बात है । दूसरी बात यह कही गई कि जिस वक्त श्री मोहन लाल गौतम तथा उनके कुछ मित्र राज्यपाल महोदय से बात कर रहे थे तो कोई टेलीफोन दिल्ली से गया था और उसके लिये यह बताया गया कि यह 2 बज कर 40 मिनट पर . . .

श्री एस० डी० मिश्र : लखनऊ से दिल्ली आया था ।

श्री पृथ्वीनाथ : गवर्नर महोदय ने इस सिलसिले में एक बयान दिया है । श्री मोहन लाल गौतम की व्यक्तिगत जानकारी कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा कि उनसे किसी सज्जन ने कहा है कि ऐसा है । राज्यपाल महोदय ने इस विषय में बयान दिया है कि मेरी दिल्ली से बात हुई है लेकिन वह इसलिए थी कि कोई लखनऊ आ कर ठहरना चाहते थे, उसके सम्बन्ध में बातचीत हुई थी । मैं ऐसी आशा करता हूं कि श्री मोहन लाल गौतम ने शायद राज्यपाल महोदय का वह वक्तव्य नहीं पढ़ा होगा, अगर वह उसे पढ़ लेते तो शायद कोई ऐसी बात नही कहते । तीसरी बात जो कही गई है वह यह कही गई है कि प्राइम मिनिस्टर महोदया के कमरे में कोई मीटिंग हुई और उसमें राज्यपाल महोदय भी थे, श्री बहुगुना थे और श्री दीक्षित जी थे । उसके सम्बन्ध में मुझे तो कोई जानकारी है नहीं और न किसी अखबार में वह खबर छपी है और न किसी को यह बात मालूम है । वहां क्या बात कही गई और वहां क्या किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं है और न कोई प्रेस में छपा है किस सोर्स पर और किस बेसिस पर ये बात आज राज्य सभा में कही गई मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

दूसरा पहलू उस समस्या का जो आता है वह यह है कि गवर्नर महोदय ने जो सरकार बनाई है उसमें जो डिसक्रिशन इस्तेमाल किया है वह गलत है, यह ठीक है या नहीं, इस सम्बन्ध में मेरा पहला कहना यह है कि गवर्नर महोदय को अधिकार है कि वह जिस तरह से चाहें उस को इस्तेमाल करें बशर्ते कि भारत की सरकार

[श्री पृथ्वीनाथ]

का कोई प्रेशर उन पर न पड़ा हो लेकिन फिर भी आबजेक्टिवली हम प्रत्येक परिस्थिति को देखें और यह देखें कि गवर्नर महोदय ने जो कुछ किया है उसमें उनके डिसक्रिशन के एक्सर-साइज़ में क्या गल्ती हुई है। जिस वक्त कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये और उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी थी उसके भी दो टुकड़े हो गये तब से वहां कांग्रेस का जो बहुमत था वह खत्म हो गया था। कांग्रेस की पार्टी के 216 सदस्य थे जिनमें से 10 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था और उस वक्त उनका बहुमत अल्पमत में टर्न हो गया था। उसके बाद बार-बार राज्यपाल महोदय से कहा गया कि आप असेम्बली की मीटिंग तुरंत बुलायें ताकि ट्रायल आफ स्ट्रेंथ हो जाय, श्री सी० बी० गुप्ता की सरकार का बहुमत नही है लेकिन राज्यपाल महोदय ने कुछ भी न सुन कर मुख्य मंत्री महोदय की बात को माना और 11 फरवरी की तारीख रखी गई। उपसभापति महोदय, यह बात मैं राज्य सभा की जानकारी में लाऊंगा कि 30 अगस्त की मीटिंग होने के बाद श्री चन्द्रभानु गुप्त ने असेम्बली की कोई मीटिंग नहीं बुलाई और जब छः महीने पूरे होने को आते थे—28 तारीख को आखिरी तारीख थी—तो 15 दिन पहले 11 फरवरी को हाउस बुलाया गया। और दूसरी ताज्जुब की बात यह थी कि 11 फरवरी का जो समन था वह दिसम्बर में ही इश्यू कर दिया गया था। ज्यादा-से-ज्यादा 5 या 6 हफ्ते का समन देते हैं लेकिन 10 हफ्ते या 11 हफ्ते पहले समन दिया गया लेकिन राज्यपाल महोदय ने बार-बार कहने के बावजूद, उनके खिलाफ तरह-तरह के प्रचार होने के बावजूद, नहीं सुना और उनका एक ही रवैया था; एक ही कहना था कि जो मुख्य मंत्री महोदय कहेंगे उनकी उस राय से मैं अपने को बाध्य मानूंगा।

अब श्री चन्द्रभानु गुप्त ने उसके बाद क्या किया। अपनी मैजारिटी, अपना बहुमत बनाने के लिये कुछ राजनैतिक पार्टियों से सांठगांठ की और सांठगांठ का नतीजा हुआ कि कुछ प्रोग्राम बनाया गया और प्रोग्राम के मुताबिक आर्डिनेंस पास हुये। उपसभापति महोदय, गौर करने की बात है कि सवा छः एकड़ की मालगुजारी लगान माफ करने का आर्डिनेंस पास किया गया—लगान की माफी करने के मेरिट्स और डिमेरिट्स में मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता, उसको इस वक्त डिसकस करना नहीं चाहता लेकिन यह बताना चाहता हूं कि वह मालगुजारी जो वसूल की जायगी वह अप्रैल के बाद मई में वसूल की जायगी। तो राज्यपाल महोदय को इस बात को मालूम करना था कि क्या आवश्यकता थी कि इतनी जल्दी में आर्डिनेंस पास किया जाय जब कि उसके पहले असेम्बली आने वाली थी और उसकी कोई अरजेंसी नहीं थी। चन्द्रभानु गुप्त जी ने जो आर्डिनेंस पास करना चाहा था वह केवल इसलिये करना चाहते थे कि जिस राजनैतिक पार्टी से वह गठबन्धन कर रहे थे उस पार्टी की पहली शर्त यह थी कि आपको यह काम करना होगा। इसी तरह से किसी दूसरी पार्टी को खुश करने के लिये जो दूसरा टैक्स था उसको भी माफ करने के लिये आर्डिनेंस पास किया गया। हम लोग यह महसूस कर रहे थे कि गवर्नर महोदय को चन्द्रभानु गुप्त जी के इस मशविरे को नही मानना चाहिये और इस मशविरे को मान कर वह चन्द्रभानु गुप्त जी की अल्पमत सरकार को बहुमत से बनाने में मदद कर रहे थे। आखीर को जब 11 फरवरी को असेम्बली की मीटिंग का अंतिम समय आया तो 10 फरवरी को चन्द्रभानु गुप्त जी ने इस्तीफा दे दिया। 10 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उस इस्तीफे के सम्बन्ध में यहां यह कहा गया कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया वह चौधरी चरण सिंह के मशविरे से दिया। मैं यह बात साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि इस मसले में चौधरी चरण सिंह का कोई मशविरा नही था। यह भी इस सदन में कहा गया कि

चौधरी चरण सिंह की तरफ से दो तीन व्यक्ति मिले, जिनका यहां नाम भी लिया गया है। मेरी पूरी जानकारी है और उस बेसिस पर मैं कहता हूं कि यह बात सोलहों आने गलत है। श्री चन्द्रभानु गुप्त की तरफ से जो लोग आये हैं जिन्होंने बातें करने की कोशिश की है उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है, मैं उन साथियों का नाम नहीं लेता जो कि यहां मौजूद नहीं हैं, मैं उनके नाम लेने की गलती नहीं करूंगा, लेकिन श्री चन्द्रभानु गुप्त के बहुत से लोग आयें। लेकिन राज नैतिक पार्टियोंके लिये ऐसी कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं है। बात यह है कि 10 तारीख को श्री चन्द्रभानु गुप्त ने अपने मन में तय कर लिया कि वह 11 तारीख को असेम्बली को फेस नहीं करते, 10 फरवरी के पहले तक वह हमेशा कोशिश करते रहे कि मेरा बहुमत हो और असेम्बली का इजलास हो लेकिन जब असेम्बली को फेस करने की बात आई तो इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया रात को 9 बजे, साढ़े 9 बजे और 10 बजे चौधरी चरण सिंह से मुलाकात हुई। इस सदन में कहा गया कि चौधरी चरण सिंह से प्रोग्राम तय हो गया था, कार्यक्रम पर सहमति हो गई थी। साढ़े दस बजे चौधरी चरण सिंह ने गुप्ता जी को साफ कह दिया था कि जो प्रोग्राम आपने बताया है वह मुझसे पूरा नही होने वाला है और अगले दिन अखबार में वह खबर छपी तो साफ-साफ चरण सिंह जी ने चिट्ठी लिख दी कि यह प्रोग्राम है तो मैं कोई सरकार बनाने को तैयार नहीं हूं, अगर गवर्नर महोदय बुलायेंगे तो...

श्री निरंजन वर्मा : क्या श्रीमान सेठ साहब इस बात को मंजूर करेंगे कि चौधरी चरण सिंह श्री चन्द्र भानु गुप्त के हमेशा खिलाफ रहे तो चरण सिंह जी ने गुप्त जी की प्रशंसा में सर्टिफिकेट कैसे दे दिया था।

श्री पृथ्वीनाथ : उपसभापति महोदय, मैं सारी बातें आपको बताता हूं। श्री निरंजन वर्मा मुझे पूरी बात कह लेने दें उसके बाद उनकी बात का जवाब देने के लिये मैं आपकी इजाजत चाहूंगा, वह आप दे देंगे।

बात यह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह ने उनके बयान को देखा। मैं यह बात कहूंगा कि चूंकि गुप्ता जी के स्वास्थ्य को पूछने आये थे तो उनसे मिले थे और वह बात साफ कह दी थी और वही बात चिटठी में लिखी है, उस चिट्ठी का जवाब गप्ता जी ने दिया तो उन्होंने कभी नही कहा कि मैंने इस्तीफा आपके मशविरे मे दिया।

श्री एस० डी० मिश्र : श्रीमन्, एक बात मुझे पूछनी है। एक बात आप बता दें।

श्री उपसभापति : अभी इंटरप्शन नही कीजिये, उनको खत्म करने दीजिये।

श्री एस० डी० मिश्र : श्री चरण सिंह की ओर से बयान दे रहे हैं, यह बता दें, उनके साथी हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि 10 तारीख को जब साढ़े आठ बजे गवर्नर के पास वह रेजिगनेशन गया उसके पहले छः बजे शाम को चरण सिंह ने जो ड्राफ्ट रेजिगनेशन का है उसको देखा, अपने घर में, चरण सिंह के घर में, कोई फ्रैंड हैं, उनका नाम मैं फिर नही लेता हूं, ले गये, उसको उन्होंने देखा ही नहीं था, उसमें उन्होंने स्वयं संशोधन एक दो बातों में नहीं किया था? और क्या यह सही नहीं है कि चरण सिंह ने स्वयं इस प्रोग्राम को स्वीकार किया? मुझे तो मालूम नहीं लेकिन क्या यह सही नहीं है कि रेजिगनेशन के अरेंजमेंट में उन्होंने मुख्य मंत्री पद को स्वीकार करने की स्वीकृति दी थी?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has no time to reply to allthose questions.

SHRI S. D. MISRA : Let him reply.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has no time.

श्री पृथ्वीनाथ : उपसभापति जी, इन सवालों के संबंध में मेरे लायक दोस्त विवाद उठा रहे हैं ।

श्री उपसभापति : आप अपना भाषण एक सेन्टेन्स में खलास कर दीजिए ।

श्री पृथ्वीनाथ : जो कारेस्पोन्डेन्स हुई श्री चरण सिंह और श्री चन्द्रभानु गुप्त के बीच में उसमें यह बात साफ-साफ जाहिर है । उसमें एक-एक बात साफ-साफ कही गई है कि चरणसिंह उनसे क्यों मिलने गये . . .

श्री उपसभापति : देखिये, अब आप अपना भाषण खलास कर दीजिए ।

श्री पृथ्वीनाथ : अब सवाल यह रह जाता है कि बार-बार कहा गया कि गवर्नर साहब ने फौरन उनको क्यों नहीं बुला लिया । गवर्नर साहब को 10 तारीख की रात को बयान दिया गया, 11 तारीख को श्री कमलापति त्रिपाठी ने चैलेन्ज किया और कहा मुझे बुलाना चाहिये । अब असेसमेन्ट शुरू हो गया, असेसमेंट होने के बाद, एक बात जो कहीं नहीं कही गई और जो बड़ी इन्टरेस्टिंग बात है, वह है कि चन्द्रभानु गुप्त ने गवर्नर महोदय को फिर लिखा कि मैंने जो अपनी सिफारिश लिखी उसको मैं अगेन्स्ट में रखता हूं । अभी वह अगेन्स्ट में हैं . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That will do now. Please finish your last sentence.

SHRI PRITHVI NATH : Two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You have taken eleven minutes already. Only the last sentence now.

श्री पृथ्वीनाथ : मैं सिर्फ एक ऐसी बात कहना चाहता हूं जिसका कोई जिक्र नहीं हुआ है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : If the House wants to sit longer, I have no objection.

श्री पृथ्वीनाथ : मुख्य मंत्री होते हुए गुप्त जी ने यह लिख कर दिया कि चरण सिंह जी को बहैसियत विरोधी दल के नेता के बुलाया जाय । इसके बाद 14 तारीख को वह लिखते हैं कि मैंने चरण सिंह जी से क्लेरिफिकेशन सीक किया है, जब तक क्लेरिफिकेशन न आ जाये, मेरी सिफारिश को अगेन्स्ट रखा जाये । इसके बाद जब गवर्नर साहब ने . . .

श्री उपसभापति : बस, बहुत हो गया । अब आप समाप्त कर दीजिए ।

श्री पृथ्वीनाथ : एक सेन्टेन्स में कह दूंगा । 17 तारीख को जब उन्होंने गिरधारी लाल और चरण सिंह को बुला लिया उसके बाद एक घंटा असेसमेन्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि चरण सिंह जी को बुलाया जाय । शायद गुप्त जी आशा करते थे कि गवर्नर उनकी बात मानता था, लेकिन अगर आज उन्होंने ऐसी बात की जो गवर्नर ने पसन्द नहीं किया तो गवर्नर की ईमानदारी पर शक करना ठीक नहीं है ।

SHRI BANKA BEHARY DAS (Orissa) : Mr. Deputy Chairman, often in this House we have alleged that Govenors have been utilised by the Centre either for toppling or for forming different Ministries in different States. In that connection I would like to repeat that because of these incidents a jungle of precedents has been created in this country and a Governor's discretion has been made flexible. In one State—West Bengal—the Governor has tried to influence Mr. Ajoy Mukherji to convene the Assembly earlier than was scheduled whereas in another State—U.P.—the Governor, Mr. Gopala Reddi, has argued that he has no authority to force Mr. C. B. Gupta to summon the Assembly in U.P. earlier than was scheduled. So, in this process so many precedents have been created; and all the precedents have been absolutely contrary to each other and it is very difficult to say what a Governor's discretion is whether the discretion of Governors has been properly utilised in this country or not. That is why in this House we have always demanded that an instrument of instructions should be given after consulting the Law Ministry, after consulting the various parties in Parliament, so that the Governors can behave impartially as far as possible in

spite of the fact that there will be constant pressures on them from the Centre, from the party whichever is in power at the Centre. I am astonished to see that in the name of discretion they want to have all those flexible powers o utilise them to suit different circumstarces and different bosses who will be appointing them or displacing them. I do not want to say more about it. But here again I demand that in the changing situation the Home Minister should seriously think that a guideline should be there for the Governors as far as their discretionary powers are concerned.

As regards the situation in Bihar, we are also a party, to a certain extent, involved in the formation of the new Ministry in that State though we have not participated in that Ministry. Two arguments which are seemingly logical have been advanced in this House. One argument is what compelled the Governor of the State to send two reports to the Centre, one on February 11 and another just three days after, on February 14. And the other argument has been that when there were other persons also claiming that they had majority in Bihar, why the Governor did not wait and try to assess the situation, whether Mr. Daroga Rai had the majority or somebody else had the majority. These are the two arguments which are being hurled in this House as also outside this House. Now I want to reply to those questions. Number one. There was absolutely a qualitative change in the situation in Bihar between February 11 and 14. I know that on February 10 the General Secretary of my party, Mr. Prem Bhasin, met the Governor and the Governor asked him whether he was prepared to give in writing that the PSP was going to support the Daroga Rai Ministry. On that day Mr. Prem Bhasin informed the Governor that he was not prepared to give that in writing just then. On February 10 the Governor also clearly indicated to us that he was going to report to the Centre in one or two days as the Parliament was going to meet on February 20. He said he could not delay sending his report to the Centre. So, it was evident on the 10th itself in the course of our discussion that the Governor was going to make a report in one or two days. And on that day neither the PSP nor the CPI was prepared to give its complete support to Mr. Daroga Rai in the formation of a Ministry. Naturally the Governor's report came on February 11 in which he clearly stated that though Mr. Daroga Rai claimed the support of the Communist Party and the PSP, he was only able to produce the letter of the All-India Jharkhand Party and not of the Communist Party, and the PSP. So this was the situation that was obtaining on February 11, and at that time the Governor clearly told us also that though he was going to send that report to the President, if during this period the situation changed and the political parties made up their mind regarding the formation of a Ministry, then, he was prepared to send another report in a short time. This was clearly indicated by the Governor of Bihar on February 10. All of us knew that. In two or three days after that the CPI and the PSP finally decided, in view of the conditions that were obtaining in Bihar at that moment, to support the Daroga Rai Ministry, and that was given in writing to the Governor on February 13. So, when two major all-India parties which are absolutely dependable not only in terms of the Governor's report, but in all other aspects also, decided in writing to support the Daroga Rai Ministry, then, it means there was absolutely a qualitative change in the situation. So the Governor took into account definitely the 43 members of both the parties when they decided to support the Daroga Rai Ministry. So, naturally on February 14 the Governor gave his second report. There is absolutely nothing incongruous and there is nothing conspiratorial in the circumstances of the two reports that came with a gap of just three days.

Then, the other argument has been that if Mr. Daroga Rai claimed a majority with some undependable elements, what about others then ? Because, the SDV at that time claimed that it had a majority. Even the SVD leader, Mr. Tiwari and Mr. Karpuri Thakur, went to the Governor on the 13th, just one day before the second report of the Governor, and wanted one week's time. Was it not, therefore, evident that Mr. Daroga Rai with the signatures and the support of some political parties and members could show the Governor that he commanded a majority on that day in the State? On that date there was neither the SVD nor any other party who could

[Shri Banka Behary Das]

go and satisfy the Governor that they commanded the majority. When it is a fact that the then SVD leader, Mr. Tiwari, along with Mr. Karpuri Thakur, the Chairman of the SSP, went to the Governor on the 13th and said that they wanted one week's time for the formation of a Ministry while on the other hand, there was another person who could produce the signatures and consent of different political parties showing that he commanded the majority, there cannot be any case for anybody to complain that Mr. Daroga Rai at that time had no majority or that somebody else had the majority. Even though the SVD leader, who went to the Governor, claimed that he commanded the support of 175 members, he did not produce anything from any political party in writing at that time. So, it is absolutely clear that on that day, on February 14, when this report of the Governor came, while on the one hand Mr. Daroga Rai could satisfy the Governor of the number of his supporters—171 supporters—on the other there was no other person in Bihar politics who could show that he commanded the majority in the House. Who does not know that the SVD that was formed in Bihar would not function even for one or two days? Even one of the constituents of the SVD in a public statement attacked another political party belonging to the SVD that that party is a faceless, heartless and headless one. So this was the state of affairs in Bihar though some SVD was floated. When that was the alternative before the Governor, I think the Governor acted properly in his discretion, although I am not going to say that all the actions of the Governors in the different States are according to democratic principles. I may warn in this connection that the Government which has been formed in Bihar with our support is definitely on the basis of a common minimum programme and I can warn here that if that is not implemented properly, the Government cannot expect any unconditional support from us. So I hope and trust that the Daroga Rai Government will try to implement those programmes in the proper spirit and Bihar will be given a stable and progressive Government and not a Government headed by reactionary parties or groups.

I now come to U.P. I am not going to discuss much about it because it has been discussed at length but I am not so much ashamed about the behaviour of the Governor there. Rather all of us should be ashamed of the Chief Minister's conduct, despite some parties' support to the present Chief Minister who wanted to play with all the political parties—both the wings of the Congress. All of us should be ashamed and I may say that even the Congress Organisation has attacked the Governor of U.P. as regards the formation of the Ministry headed by Mr. Charan Singh but they have offered the same temptation again to Mr. Charan Singh that if he can defect, another Ministry can come in. Absolutely it is a dangerous situation that is obtaining in U.P. and a person, because he has been able to muster a strength of 98 because of the particular circumstance in the politics of U.P., is now the Chief Minister. He has tried to play not only with the Congress Organisation but with the Congress Ruling Party and other political parties. So I will say that all of us should be ashamed about the Chief Minister, Mr. Charan Singh, and it will be much better if all of us can see that such persons do not head any Government, wheter in U.P. or in any other State of the country.

SHRI S. N. MISHRA : Mr. Deputy Chairman, I am a little unwell and so I would take a little longer, maybe two minutes longer than the time prescribed for me. Now I would submit to you in the very beginning that it is not a pleasure for us to bring in the Governors for a discussion in the House. In honouring this great institution of Governor, this is our firm opinion, we honour ourselves and in unduly running down the Governors, we show disrespect ourselves or run down ourselves. But at the same time I submit that if we do not criticise what we consider to be the wrong conduct of the Governors, then we would be doing a great injustice the Constitution and to ourselves. Therefore it is in that spirit of duty and loyalty to the Constitution that I am going to make a few submissions when I am going to discuss the conduct of two Governors, that is, the Governor of U.P., and the Governor of Bihar. When I broach this subject, and I come to discuss the conduct of the Governors, I am aware of the fact

that we are functioning under certain kinds of limitations and we really do not know whether we can continue to function within those limitations. Whatever accusations we might make, there might be a reply that the Governor has exercised his discretion quite well and this is not challengeable in any manner. That is the reply usually given on the basis of the present provisions of the Constitution. If I say even on oath that a particular Governor told me such and such thing at a particular time—only 40 minutes before the oath-taking—there will be no body who can say from the side of the Government whether he did say or not and therefore I would be making a fool of myself if I make an accusation of that kind because that is bound to fall flat and that would not work. Many Members on the basis of their own personal experiences have said what the Governors of these two States had told them and how they changed their opinions within a few minutes. So I would submit that unless there are certain safeguards against such irresponsible conduct of the Governors, we cannot expect that a truly representative Government would be functioning in many of the States. We have certain provisions for the impeachment of the conduct of the President but we cannot impeach the conduct of a Governor. And if we want to impeach the conduct of the Governor, we will perhaps have to impeach the President Otherwise there would be no other go for us. We cannot bring a censure motion so far the Central Government is concerned.

AN HON. MEMBER: Only in the other House, it can be done.

SHRI S. N. MISHRA : What I mean is not even the other House. I would not in theory concede that the Governor is the representative of the Central Government. Therefore we cannot bring in a motion of no-confidence in the Central Government even if I belonged to the other House. That is the difficulty which confronts us when we discuss the conduct of the Governor and so it becomes a futile attempt. We are therefore in a great predicament. Certain Members have suggested that there should be some guidelines for the Governors in such circumstances. May I submit that those guidelines also would not be allowed to work because of the way in which the Central authority and Central power is working now. The story of the defilement of the constitution begins not in Patna or Lucknow. It begins right here in Delhi and if Gangotri is sullied, how can you expect the Ganges to be pure at Lucknow or Patna? The main thing is this the process of pollution begins here. And what is to be done about it? Then again there is another question that I can take on another plane. I am raising a constitutional issue. I cannot discuss the conduct of the Governor in that way and it becomes a pastime and particularly for the press, I must say, the way in which the discussions in the other House had been treated in the press this morning, it seems as if the crucial issues were not raised. From the side of the Government whatever had been said, I must say, they did not do justice to the points raised there. Even then there have been screaming headlines in the press that the debate had fallen flat or that the issues had not been dealt with squarely in the debate that took place in the other House. What I would submit is that whenever any difficulty arises with regard to the assessment of the strength of parties or with regard to the assessment of majority, then a way must be found. This is my submission with regard to the Constitutional Amendment that may be brought about; a way must be found to test the majority in the House itself; otherwise there is no other go for us; there is no other way or safeguard against the irresponsible conduct of the Governors. What has happened in Patna? There are some prominent facts that must be noted carefully.

I am giving incontrovertible facts and let the hon. Members note these facts very carefully. It is an incontrovertible fact that the Governor sat tightly on a list submitted by the leader of the joint Congress Legislature Party there in Patna for pretty seven or eight months. This is fact number one. Fact number two is that the Governor said to the Chairman of the S.S.P. only a few weeks back, may be two weeks back : "I am not going to repeat the same mistake of taking a decision in a hurry lest I have to repent it at leisure." This is number two. And this was not contradicted.

SHRI AKBAR ALI KHAN : Are we discussing the conduct of the Governor, Mr. Mishra?

SHRI S. N. MISHRA : What else am I doing?

SHRI AKBAR ALI KHAN : It should not be discussed.

SHRI S. N. MISHRA : Well, unless I discuss the conduct of the Governors in certain circumstances I would not be doing justice to my duty by the Constitution. I think you were not attentive enough when I was making my prefactory remarks.

Then, Mr. Deputy Chairman, the third point which must be noted is that the Governor has said in his letter dated February 11 that there was no reasonable prospect of any stable Government being formed, and that must be held firmly before our minds' eye. And then what does this Governor say in that letter? Since the proclamation is to expire on the 27th of this month "I cannot afford to wait any longer and therefore I am making this recommendation." Mark it. These are not my words. "I cannot wait any longer", this is what the Governor said on the 11th February. But when it comes to the 14th of February the same Governor has to wait—I really do not know why. On the 11th he could not wait for two days. And by that time another list was submitted to the Governor by the Chairman of the S.S.P., who also happened to be the provisional Chairman of the S.V.D. saying that he had got the support of 175 members. The Governor, who says earlier that he would not take any decision in a hurry, the same Governor does not care to wait to test the veracity of the two lists. Now it is said that Shri Upendra Nath Verma, Chairman of the S.S.P., did not submit any list. But is also admitted by the Governor in his letter that he had asked for time. Now could not time be reasonably given in this matter, particularly when you recall to your mind that the same Governor had said that he would not try to take any decision in a hurry? But this Governor does not give reasonable time to the other person who claims the support of 175 members. Now to what conclusion ever we bound to be driven to in these circumstances ? The circumstances clearly indicate that the Governor here was bent upon creating circumstances favourable to a party which owes allegiance to the Centre. Now my hon. friends of the Praja Socialist Party, or ofthe Communist Party, because they also happen to be somewhat associated with it, may try to gloss over this matter. But the situation is so rapidly changing that they may well have to repent if they approve of the conduct of the Governor in a blanket manner.

Now here one thing has been pointed out by the Governor in his letter dated February 14—he has said that 17 members in the list submitted by Shri Daroga Prasad Rai, the present Chief Minister, do not seem to be of dependable loyalty. It has been clearly mentioned by many Members that, even according to the estimate of the Governor, according to the assessment of the loyalty by the Governor, the list submitted by Shri Daroga Prasad Rai was not a list of majority support to him the list was only of 154 persons. Now this is a point which cannot be sidetracked. I would like to now from the Government whether it is not a minority Government which has been installed there by the Governor. And if a minority Government has been installed by the Governor there, how can Governor say in his letter that Shri Daroga Prasad Rai is enjoying a comfortable majority, that I do not understand. I know that the hon. the Home Minister has in the other House spoke about "a party which is likely to have the support of a majority." I know he has used the word 'likely' etc. But these are not the words used by the Governor. Here the Governor says that a particular person did have the support of a comfortable majority. Now here is an assertion by the Governor which is not supported by facts. And what exactly this Governor can be asked to do in the circumstances? In what way this House can put this kind of Governor on the right track ? In what way this House can pull up this Governor who makes a statement which is at variance with facts and on the basis of the simple arithmetic that he has himself given in the circumstances of this case? Further, Mr. Deputy Chairman, I had frantic calls from Patna and I had to seek an interview with the President. And when I came to know of facts, and before the second report was submitted to the President, I had an opportunity to meet the President, I had to do that because there were the reports that almost hourly telephone calls were being made from Delhi to Patna and the Governor was under heavy pressure for inviting a particular person to form the

Government of Bihar, I informed the President about it in advance of the receipt the report from the Governor. And that has also been the accusation in the case of Uttar Pradesh. In both the cases we have almost the same kind of story that there were heavy pressures working from Delhi. So I would submit that, in the case of Bihar, even now it is a minority Government; it must be admitted that it is a minority Government that has been installed by the Governor there and the Governor has made a statement which is not true. A Governor who makes a statement which is not true cannot have the confidence of this House; that is very clear. He cannot expect the support or confidence of this House but, since we have no manner of pulling up this Governor, we are helpless, and that is the only thing that I can say.

Now coming to Uttar Pradesh, there we have got now a Chief Minister who, as has been very aptly pointed out by my hon. friend, Mr. Banka Behary Das, is almost like Henry VIII, husband, widower and a bridegroom, all within twenty-four hours. It is said that Henry VIII was all the three within twenty-four hours. And this is the kind of Chief Minister who has been installed there with the support of the mighty Prime Minister supported by her wise Home Minister here. And how did it come about? Here again the Governor did not invite the persons. I know the Government side has always the knack of glossing over facts. Now again, if it is sought to be explained away by saying that the Governor has every right not to invite any person then, again I will have to throw up my hands in despair. But the House cannot feel convinced on that account, by that kind of explanation on the basis of this all-comprehensive word 'discretion'. With regard to 'discretion',—there also I must tell you that any legal interpretation of the term 'discretion' extends only to the failure of the constitutional machinery. I would not admit that 'discretion' extends also to the restoration of the constitutional machinery. The words in the Constitution simply mention the failure of the constitutional machinery. At another opportunity I will come with my own theory that it does not relate, on the basis of the wording of the Constitution, to the restoration of the constitutional machinery also.

If one thinks that the failure of the constitutional machinery also includes the restoration of constitutional machinery I will have my own doubts about it. But I am coming to another aspect.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You must wind up now.

SHRI S. N. MISHRA : Just a one minute. This is a very interesting subject. Mr. Deputy Chairman, you would bear in mind that when a list of 275 to 300 persons was submitted to the Governor, the Governor was not pleased to invite Shri Charan Singh to form the Ministry. But the same Governor, when Chaudhri Charan Singh is supported by the Prime Minister's party, does not lose even a moment's time in inviting him to form the Government. This is the kind of discrimination that the Governor of that particular State makes in favour of one party and against another party and that is a point whih sticks very much in our minds.

Now, this Governor did come to Delhi. That point has been made and that must be repeated for when a Governor makes a pilgrimage to Delhi he comes at Government cost and when he comes at Government cost we should be told what was the nature of his mission to Delhi. Nobody here is prepared to share with us the information about the nature of the mission which the Governor undertook. If he come to Delhi we must know what it was about, whom he consulted and who gave him what kind of advice. Much of the advice can be held secret but even so the broad nature of his mission must be made known to us. And again if it was for advice from the Government than I must say that the Government here is trying to manipulate things in the States which is contrary to the spirit of the Constitution. As I submitted yesterday the Central Government is not only geographically central but it ought to remain politically central also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That will do.

SHRI S. N. MISHRA : And if it does not remain politically central, then I must say with all humility to my hon. friend, the Home Minister, that there will not be any stability in a federal set-up like this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : That is enough now.

SHRI S. N. MISHRA : Only one word. This is not a matter which can be brushed aside in a few minutes like this. We have witnessed how the valuable time of the House is allowed to be wasted sometimes in trivialities. Here I am in the midst of a serious discussion and if it takes a few minutes more, I hope, I will have this time.

Now, the Governor did come to Delhi. At that time we did not know. We come to know only from the press reports; nothing is made known to us. What was it about that the Governor came here? And this Governor of Uttar Pradesh change his mind and that is on the testimony of the most authoritative persons who had happened to meet the Governor. The same day till one o'clock the Governor says that he will not touch with a barge pole the list submitted by Mr. Kamalapati Tripathi; but the same Governor within a few minutes' time, within forty minutes in fact, changes his mind and instals the Government. Some friends say, as it has been done in Kerala, the majority would be established later on. Thereby you are trying to corrupt the Members. This is the process by which corruption of the Members takes place. The Home Minister here appoints a Committee for controlling defections and so on but by installing a Government which does not enjoy majority you place a particular person in a position in which he can bide time and influence Members through power and patronage. This is most saddening and I must say with great agony in my mind that this process of defilement of the great institution of Governors is indeed a sad chapter that has been encouraged by the present Government here.

Thank you.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I am glad indeed that in this House also we have got an opportunity to discuss the role of the Governors in both the States, U.P. and Bihar. Unfortunately, the Member who initiated the debate has conveniently decided to be absent from the House.

श्री निरंजन वर्मा : मैं तो बैठा हूं ।

SHRI Y. B. CHAVAN : It is not a question of the party being represented. The Member who has moved the motion in all seriousness should be present here. That only shows the degree of seriousness with which the motion was moved.

Apart from that, I am glad that the speech which was delivered last in the debate, Shri S.N. Mishra at least attempted to make some case for the motion. But I would like to try to be objective in this matter because I do not propose to discuss the personalitie involved in the politics here though I m y refer to them because some points relating to them have been made. I do not hold a brief for either one party or the other. I think it is necessary for me as a member of the Central Government to see that the role that a Governor has to play in the formation of the State Governments is objective and constitutionally correct. That is one thing which we have to take care of. Unfortunately some lighthearted remarks were made about the Central Government and the Prime Minister and even the Home Minister. I would like to assure this hon. House that in the whole drama of formation of Governments in Bihar and Uttar Pradesh the Central Government, the Prime Minister, the Home Minister and other members of the Government absolutely, directly or indirectly, played no part at all. I would like to give that very solemn assurance. Merely drawing some light inferences which are politically motivated does not prove the case. The way Mr. S. N. Mishra started —he started by saying that Gangotri was polluted and all that— I thought possibly he was likely to prove something which we have done here. I would like to go into this matter a little later.

SHRI S. N. MISHRA : If there is time I would do that.

SHRI Y. B. CHAVAN : When you do that I will reply to that also. When you said

that Gangotri is polluted I thought you would come out forthwith with certain facts which you did not. I expected a little more serious statement from the hon. Member because I respect him for his seriousness.

Sir, I think the question falls into two categories—what is the constitutional position and what are the facts. I think about the constitutional position there should not be two opinions about it. I do not know but when Shri Mishra said that really speaking the whole thing should be tested on the floor of the House does it mean before forming the Government it should be tested?

SHRI S. N. MISHRA : There must be some way found for that.

SHRI Y. B. CHAVAN : Some way may be found but I am here to interpret and work the Constitution as it is.

SHRI S. N. MISHRA : In fact, I began by saying that.

SHRI Y. B. CHAVAN : If the Constitution is to be changed, in what manner it should be changed, I would leave it to the Constitutional pundits.

Now, what is the present constitutional position? The present constitutional position is—I need not quote—article 164(2) lays down the fundamental principle that the Council of Ministers is collectively responsible to the legislature. This shows that the person who is to be nominated or selected or summoned to become the Chief Minister should have the capacity to command a majority in the legislature. This is a fundamental thing. This is an indirect command on the Governor that he must make an assessment before summoning a person to become Chief Minister and convince himself that the man is likely to get—when I say 'likely to get' it means naturally it is a matter which will happen in the future and that is why I use the word 'likely'— a majority in the legislature. Therefore my use of the word 'likely' should not be misunderstood. When I say 'likely' it means naturally that the thing would happen in the future. Certainly the Governor has to convince himself that the person he is asking to become the Chief Minister is in a position to command a majority in the House. That is the position.

Now, Sir, some Members made a suggestion to me and asked : Why is it that the Government has not tried to formulate certain guidelines? I have already many times mentioned the facts on the floor of the House, but Members are apt to forget matters. In 1967 this question came up in a discussion here on the floor of the House when the matter of Rajasthan became a little controversial. They asked me : Why is it that you are not making an attempt to formulate certain guidelines? I said I would certainly make serious efforts about it. I did make efforts. I called upon some very eminent jurists in the country and I wrote to the late Shri M. C. Mahajan, a former Chief Justice of India, Mr. A. K. Sarkar, another ex-Chief Justice of India, Mr. M. C. Setalvad, who is a distinguished Member of this honourable House and a very leading jurist of the country, Mr. P. B. Gajendragadkar, who is again an ex-Chief Justice of India, and Mr. H. M. Seervai, a great constitutional lawyer and the Advocate-General of Bombay. I requested them to advise me on the principles that a Governor ought to follow in appointing the Chief Minister when no party secures an absolute majority at a general election. The replies received from these experts indicated certain consensus. Three points emerged out of these disussions. Two important points which are relevant to the present debate are that the alignment of independents should not be ignored while assessing as to who is likely to constitute the majority. In an Assembly besides the organised members, there are also independent members. That should be the attitude of the Governor about these independent members? Their advice was that they also are members of the Legislature and so they should not be ignored in making the assessment. The second point was that the Governor should invite the person, who has been found by him as a result of his sounding, to be the most likely person to command a stable majority in the Legislature. He should form the Government. The third point that they had urged was that after such a situation the Governor should take care to see that the Assembly is called immediately to test the position.

[Shri Y. B. Chavan]

Unfortunately these guidelines could not be sent to the Governors. I wrote to all the leaders of the parties in Parliament and requested them to send their views on it...

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Including Dr. Bhai Mahavir.

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not remember it, but I must have written to his party leader. Unfortunately till this day I have not received a reply to that . . .

SHRI S. N. MISHRA : Did you write to me ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Unfortunately you became a party later. This is my open invitation even now. I did not convey these guidelines officially to the Governors because unless I had some sort of agreement with the parties concerned, I did not want to put forward guidelines as from a party Government. I did not want to take that position. Now, Sir, even the consensus, which has emerged as a result of discussions among the jurists in this country, is that ultimately the Governor has to choose a person who is likely to command a stable majority in the House. This is the constitutional position. As far as the present Constitution is concerned, this is the position. I hope Mr. S. N. Mishra does not dispute it.

SHRI S. N. MISHRA : May I know whether the advice was elicited before all this fall of Ministries took places with great rapidity? All this rapid fall of Ministries took place after 1967.

SHRI Y. B. CHAVAN : Quite right, but this discussion took place in the context of Rajasthan. When this discussion was going on the toppling of governments was mentioned. It was a very fast development in this country. This was not something new. Whether there is the fall of one government or ten governments, ultimately the constitutional position does not change. The constitutional position remains the same. This is the basic constitutional position. Now, what the Governors have done in this particular matter is a matter of fact. I do not hold brief for anybody. Now, what is the charge against the Central Government? His point is, why is it that the Governor of U.P. decided to come to Delhi? I do not know why he decided to come to Delhi. We could not ban people from coming to Delhi. As he said, Delhi is a geographical centre. People are attracted to Delhi, but I do not know why. Mr. Arjun Arora said that it is a very fascinating place. Possibly so, but I want to assure this hon. House that we did not invite or we did not summon the Governor to Delhi. Somebody said that it was kept secret. It is not a fact. For the first time I knew about it from a newspaper that the U.P. Governor was leaving for Delhi. So, there was no question of inviting the Governor here.

Then, the most important thing that has to be noted is this. What started changing the whole thing in U.P. was the attitude of Mr. Charan Singh. According to him, Mr. Charan Singh is not a good person because he is in somebody else's company...

SHRI S. N. MISHRA : I have established him to be a husband, widower and a bridegroom within twenty-four hours. He is a picturesque and a romantic person.

SHRI Y. B. CHAVAN : Now, listen to me. Why do you interrupt me? I did not interrupt you. The point is Mr. Charan Singh changed position, whether for right reasons or wrong reasons, it is a different matter. It is not for me to justify or do otherwise, but it does not lie in their mouth to say that Mr. Charan Singh was a very good person and a person fit to be the Chief Minister as long as he was with Mr. Gupta or Mr. S. N. Mishra and immediately he becomes an unworthy person and a wrong leader when he wants to be guided by his own judgement in the matter.

Then, again, Mr. Charan Singh did not change after the Governor came to Delhi. I would like to refer to the letter from Mr. Charan Singh which had appeared in the press. The letter is dated 11th February. From the content of the letter it appears that the letter was written by him at eleven o'clock at night. In that he has made a reference to certain discussions he had with Dr. Ram Subhag Singh and Mr. Laxmi Raman Acharya a day before, i.e., 10th February. It was about rethinking in the mind of Mr. Charan Singh, about conti-

nuing his alliance with the Jan Sangh and SSP. It started on the 10th February in the evening and as a result of that process which started on the 10th February he writes on the 11th February very categorically. This is what he says:—

"I have had an unhappy experience of the Jan Sangh and SSP leadership in 1967-68. The talks that the Jan Sangh leader had with me this evening barely an hour ago . . .

That means that the Jan Sangh leaders seemed to have had talks with Mr. Charan Singh at 10 o'clock on the 11th, i.e., at about ten p.m. He says :—

"In practice the attitude of the SSP has convinced me that my experience of the last SVD Ministry was going to be repeated. This is just to inform you that in the circumstances it will not be possible for me to back a government that may be formed with the help or in association with Jan Sangh, SSP and your party."

He was absolutely clear in his mind as to what he should do and what he should not do and he has very categorically indicated the reasons for it. He has again said this:—

"I have, therefore, decided not to accept any invitation that I may receive from the Governor for forming the Government."

This was decided by Mr. Charan Singh before the Governor reached Delhi. There is no question of the Government of India trying to influence the decision of the Governor. Who could have influenced the decision of Mr. Charan Singh? If at all anybody is to be thanked, as I have said in the other House yesterday, for the change of mind of Mr. Charan Singh, the thanks should go to the Jan Sangh and SSP.

श्री निरंजन वर्मा : क्या आपका खयाल है कि चरण सिंह जी और गवर्नर साहब के घरों में कोई टेलीफोन नहीं था ।

श्री वाई० बी० चव्हाण : क्या बात कर रहे हैं, टेलीफोन की क्या बात है ।

श्री निरंजन वर्मा : उनमें बात हो सकती थी, बात करने के बाद में वह अपना मस्तिष्क बदल सकते थे ।

श्री वाई० बी० चव्हाण : आप तो यह समझते हैं कि सारे, सब लोग भ्रष्ट हैं, आप ही अकेले अभ्रष्ट हैं ।

श्री निरंजन वर्मा : आप गाली देने में माहिर हैं, लेकिन आपके नीचे से ज़मीन खिसक रही है, यह आप भी जानते हैं ।

श्री वाई० बी० चव्हाण : मैं जानता हूं । मेरी ज़मीन की चिन्ता आप मत कीजिये ।

श्री अर्जुन अरोड़ा : यू० पी० में मिड-टर्म इलेक्शन में जनसंघ ने 50 फीसदी सीट खो दी ।

SHRI MOHAN LAL GAUTAM : Sir, I want . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : No interruptions please.

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not want to be interrupted. I never interrupted you at all. I have not interrupted anybody. I have heard your speaches very patiently. Let me complete my reply and then you and the Vice-Chairman may decide among yourselves as to what we should do.

So, Sir, the reason why Mr. Charan Singh changed his mind lies in the history of the U.P. Governments. There is no point in blaming unnecessarily the Central Government for that. What could we have done? The earlier experience of Mr. Charan Singh about the SVD Government is mainly responsible for it. Now what was the Governor supposed to do? The point argued is that Guptaji had recommended the name of Mr. Charan Singh when he resigned. When he resigned, some people had claimed that it was the right of the retiring Chief Minister to nominate his successor because he was not defeated. This is also a very interesting and an illusory logic. I have got all respect for Shri C. B. Gupta. He was a veteran, senior member of my party. Merely because he has left the party some months ago I do not want to speak in derogatory terms about him. But the fact remains

[Shri Y. B. Chavan]
that when Guptaji decided to resign, he did not desire to oblige anybody. I think he is a realist. Gracefully he decided that as he had lost the majority in the House he should leave. That was very graceful of him. I must also say that he made a very fine judgment. It is to his credit that he made a fine political judgment that after the split in the Congress Party, the only person who could lead a stable Government in U.P. was Mr. Charan Singh. Therefore, he decided to recommend his name. Ultimately whatever happened between the different parties, the Governor has accepted the recommendation to invite Shri Charan Singh. Where was he wrong? He accepted the resignation which Guptaji gave gracefully. Also he accepted Guptaji's political judgment. I do not think there is anything wrong about it. There is nothing wrong in it at all. I should say that all these different political forces have tried something in U.P. It is good that another socialist force has emerged in U.P. Let us give it a trial. Really speaking, it is not a question of this party or that party. A fair deal must be given to the people of U.P. Everybody wanted that Mr. Charan Singh should be the leader. They saw in him the saviour of U.P. He is the right man in the right place now. Let us try to give him co-operation. Let us try to give him our good wishes. I would like the hon. Members to forget all the political anger about it, be graceful, be fair, be a sport, and give all the compliments to the Governor that he has helped to bring a stable Government. This is about U.P.

Let us come to Bihar. What is the complaint about Bihar? Sir, in Bihar there was President's rule. The Bihar Governor has written two letters, copies of which we have laid on the Table of the House. There was nothing to hide. Therefore, we decided that these letters should be placed on the Table of the House. The Governor has given in the first letter his assessment and his conclusion that there was no possibility of forming a stable Government because he wanted to convince himself about a stable majority. He also mentioned in the letter, that he had told so to Mr. Daroga Prasad Rai who had claimed the support of some political parties. I think the central thinking of the Governor appears to be that he did not want merely to depend on the individual members because he had seen certain unpredictability about their political behaviour. That is why he viewed them as undependable. He also writes of a more qualitative dependability of certain political parties, because he has found there is certainly some disciplined behaviour, there is some sort of national control over these political parties. Therefore, he has mentioned P.S.P., he has mentioned C.P.I., and also some other political parties as dependable. Dr. Mahavir made a complaint that his party was not mentioned. He has also not said that it is undependable. By implication if that is meant, I do not know about it. The main point of his argument is that he had asked Shri Daroga Rai to get in writing from these two important political parties that they supported his leadership. The others had written to him; the only two parties left were the P.S.P., and the C.P.I. Till the time on the 11th when he wrote this report there was no commitment in writing from these two parties. Naturally he was more concerned, and the hon. Member from Orissa has mentioned the talk Shri Bhasin had with the Governor when he was in Patna.

SHRI BANKA BEHARI DAS : Shri Prem Bhasin.

SHRI Y. B. CHAVAN : He was certainly concerned about one thing.

In the normal course the period of the Proclamation was coming to an end on the 26th or the 27th of this month. Naturally he wanted to warn the Central Government of the possibility of none being able to form a Government. The Government was then required to prepare a motion and bring it to this House this week. Instead of discussing the revocation probably we would have otherwise discussed the extension of the Proclamation. Naturally he sent the report. But all the time what was the duty of the Governor ? Even though he had recommended the extension of the Proclamation, his basic duty was to accept any first opportunity to invite a person. with a stable majority to form a Government, to activise the democratic and constitutional machinery. It was his duty. As a last resort he had recommended extension of the

Proclamation period. Naturally, even then he had not suggested the dissolution of the House. Even the first time when he made a recommendation for takeover of the administration, he did not recommend a dissolution. He kept the House in suspension because he always wanted to have an opportunity to allow a democratic and popular Government to be formed; to revive the constitutional working of the Government.

SHRI S. N. MISHRA : Sir, I would crave your indulgence. The Governor had said that it was being continued only for the sake of election to the Rajya Sabha.

SHRI Y. B. CHAVAN : Mr. Mishra is a very important political thinker and constitutional pandit. He mentioned the immediate reason, but the basic reason—it is not necessary to mention; it is inherent all the time in the situation. Does he mean to suggest that the Governor had in mind that immediately after the election to the Rajya Sabha the House was to be dissolved? It is not so. You must not take a literal meaning of it. The intention of the Governor has always been to seize the first opportunity to form a Government and revive the democratic functioning of the Government. It goes to the credit of the Governor that even when he had recommended the extension of the Proclamation period on the th, when he saw the possibility of formin; a stable Government, he seized upon it and went against his own recommendation to make a recommendation to the President to this effect. You must give congratulations to the Governor for his moral courage, for his honourable conduct. (*Interruption.*) The point is whether he made any miscalculations. Ther also is another drama, in both the States. There is one common drama. In both U.P. and Bihar somebody was wanted as the leader and he was refusing to be t ader. Here is another case. Shri Ramanand Tiwary was first of all appointed eader of the SVD. Somebody was trying to garland him and he was rejecting it. There was Shri Charan Singh, they wanted him to be the leader of the SVD, and he again rejected the offer. It is a story of reluctant bridegrooms in both U.P. and Bihar, I do not think that the Governors have made any mistake about it.

SHRI S. N. MISHRA : They have found a good bride in you.

SHRI Y. B. CHAVAN : Polyandry is not allowed. Some Member made the suggestion, I do not know who exactly was the person who made the suggestion, but somebody mentioned about some Rs. 50,000. This is something below dignity to make such mention, to make such reference against the Prime Minister. In this matter the Prime Minister's behaviour has been absolutely above board. What we all wanted was that the democratic functioning in the two States should be restored, because I think in all this political game who have suffered most are the people of U.P. and Bihar. Let us forget all these insignificant controversies. Let us try to rise above party loyalties and wish well of the new Governments and wish well of the Governors.

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENTS *RE* THE VISIT OF THE SOVIET DELEGATION HEADED BY H. E. MR. SKACHKOV AND *RE* THE EXPANSION OF BOKARO STEEL PLANT

MR. DEPUTY CHAIRMAN : There are certain clarifications . . .

SOME HON. MEMBERS : No, no.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Those who are interested can ask.

MR. DEP TY C IR AN : The House decided that immediately after this discussion, Members would be allowed to seek clarifications on the statements made and ther fore, it proper that we finish these two subjects on the agenda. I do not think we will take more than five minutes.

SHRI A. G. KULKARNI : Five to te minutes.

SHRI M. N. KAUL (Nominated) : Tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : This morning we had agreed that the clarifications will be asked immediately after this.

SHRI A. G. KULKARNI : Sir, it was agreed, and that was why we did not ask clarifications yesterday. It was decide